

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

बिलासपुर, रविवार 22 फरवरी 2026



Rang Jo Khushi Ban Jaye

Organic Corn Starch Scented Gulal



TECHNOLOGY BY:
NATIONAL BOTANICAL RESEARCH INSTITUTE, LUCKNOW (UP)
(A UNIT OF C.S.I.R., GOVERNMENT OF INDIA)

SCAN FOR
CORPORATE GIFTING
www.shriganeshagifts.com
SHRI GANESHA GIFTS

SHRI GANESHA GLOBAL GULAL PVT. LTD.

Raipur | Durg | Rajnandgaon | Delhi



GRAND LAUNCHING

FEB 22 2026



SPECIAL OFFERS
Receive Assured Gifts
on every Booking

OWN A FOREST



16 acres
of meticulously
planned forest living

foresta

LUXURY IN NATURE

Sarvaswa Resorts,
Old Dhamtari Road,
Tekari, Raipur



SCENIC ENTRANCE



CLUBHOUSE MIMOSA



SWIMMING POOL



ORCHID GARDEN



OLIVE GARDEN



ENVISION YOUR HOMES

PCGRERA150126002026



CORPORATE OFFICE

3rd floor, Shubham Corporate,
Infront of Airtel Office, Telibandha,
Raipur (C.G.) 492001
E-mail: shriswastikgrp@gmail.com

MARKETED BY



PRESENTED BY



IN ASSOCIATION WITH



PROMOTED BY



CALL FOR MORE DETAILS

74008 40000
www.shriswastikgroup.com

Disclaimer: Foresta is a land plotting project offering plots for sale only. All home visuals shown are artistic impressions representing potential construction possibilities on the plots. No prebuilt homes are offered for sale. Buyers purchase land to build independently.

आनंद का सच्चा भाव

18 कैरेट रेट = ₹117077/-
(75.00%)

22 कैरेट रेट = ₹142990/-
(91.60%)

24 कैरेट रेट = ₹156087/-
(99.99%)

सोने का भाव* प्रति 10 ग्राम | GST Extra

anand
Jewels
Pandri, Raipur

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

बिलासपुर, रविवार 22 फरवरी 2026

वित्त मंत्री कह चुके हैं, मंत्री बजट राशि के खर्च की गति करें तेज

पीडब्ल्यूडी ने अब तक खर्च किया 28 फीसदी बजट कई मदों में धेला खर्च नहीं, कागजों में अरबों जमा

जिया कुरैशी ॥ रायपुर छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग ने बीते दो साल जमकर खर्च किया। सरकार बनने के बाद करीब दस हजार करोड़ रुपयों के खर्च से सड़क, पुल, पुलिसिया, फ्लाइंग ओवर, भवन के निर्माण किया। लेकिन इस बार चाल धीमी हो गई है।

पीडब्ल्यूडी अब तक केवल 28 फीसदी ही खर्च कर पाया है। बजट प्रावधान 8 हजार 5 सौ 37 करोड़ रुपयों का था। इसमें से फरवरी माह तक केवल 2 हजार 354 करोड़ रुपयों का व्यय किया गया है। इतना ही नहीं, दर्जनों मद ऐसे हैं जिन पर अब तक धेला भी खर्च नहीं किया गया है। ॥ शेष पेज 5 पर



इस तरह समझें
लोक निर्माण विभाग की व्यय एवं अनुदान संबंधी जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए बजट प्रावधान 8 हजार 537 करोड़ 4 हजार 13 रुपयों का था। इसमें से 2 हजार 354 करोड़ रुपयों का व्यय किया गया है। फरवरी 2026 में 276 करोड़ 54 लाख रुपयों खर्च हुए हैं। यह आंकड़ा 27.81 प्रतिशत व्यय हुआ है।

8 हजार 537 करोड़ का बजट, अब तक खर्च केवल 2 हजार 354 करोड़

कागजों में अरबों का बजट, काम में सन्नता
राज्य की व्यय एवं अनुदान रिपोर्ट की पड़ताल में कई चौंकावने वाले तथ्य सामने आए हैं। लोक निर्माण विभाग के जिन मदों के लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया, उनमें से कई में अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। हवाई पट्टियों के निर्माण और विस्तार तथा नगर विमानन जैसे मदों में शून्य व्यय दर्ज है। इसी तरह राज्य मार्गों के विशेष अन्वेषण व सरम्मत (ओपी आरएमएसी), ग्रामीण मार्गों की ॥ शेष पेज 5 पर

जिन मदों में खर्च नहीं उनकी सूची बहुत लंबी है
लाइवहुड कॉलेज, बारापास और रिंग रोड निर्माण, भूमि अधिग्रहण मुआवजा, सड़क सुरक्षा परामर्श सेवाएं, महाविद्यालय और उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, नाबार्ड सहायता से ग्रामीण मार्ग, यहां तक कि जेल क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, जिला सैनिक बोर्ड, खेल प्रशिक्षण भवन और अस्पताल-ओपेथालय भवनों के निर्माण जैसे मदों में भी व्यय का आंकड़ा शून्य है। लोक शिक्षण संचालनालय, सरकारी शिक्षा महाविद्यालय, सीजी आईटी की स्थापना, खेल मैदानों के रखरखाव हेतु (लघु निर्माण कार्य, खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण, यूथ हॉस्टल, कक्षा और संस्कृति भवनों का ॥ शेष पेज 5 पर

खर्च की गति बढ़ाने वित्त मंत्री ने पिछले साल लिखा था मंत्रियों को पत्र
बजट की राशि खर्च करने के संबंध में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले साल सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखा था, उसमें ये बात कही गई थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2024-25 के बजट के अंतर्गत विभिन्न विभागों के मंत्रियों को पत्र लिखा है। वित्त मंत्री ने पांच मंत्रियों के विभागों में बजट की राशि के कम खर्च होने पर यह विधि लिखी थी। वित्त मंत्री चौधरी ने मंत्रियों से आग्रह किया था कि खर्च की गति बढ़ाई जाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि बजट जिस अनुपात में खर्च किया जाना चाहिए था, उस अनुपात में खर्च नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री चौधरी ने मंत्रियों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया था कि बजट के निर्धारित मापदंड के अनुसार पूंजीगत व्यय के लिए प्रत्येक तिमाही के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके अनुसार पूंजीगत व्यय होने से ही कार्यों में निरंतरता के साथ अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

खबर संक्षेप

नवी मुंबई हवाई अड्डे ने शुरू की डिजिटलायन सुविधा
मुंबई। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के लगभग दो महीने बाद 'डिजिटलायन' सेवा शुरू करने की घोषणा की है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा देश के पांच अन्य हवाईअड्डों के साथ नागर विमानन मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी डिजी यात्रा कार्यक्रम में डिजिटल रूप से शामिल हो गया है। उद्घाटन समारोह ऑनलाइन किया गया और इस मौके पर तीन यात्रियों ने प्रतीकात्मक रूप से डिजिटलायन ई-गेट का इस्तेमाल किया। और बायोमेट्रिक प्रवेश बिंदुओं पर रिबन काटा।

मादक पदार्थ गिरफ्तार के 5 सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 'स्मैक' की आपूर्ति करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरफ्तार से जुड़े पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 60 लाख रुपय मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बदयूं निवासी अमीन खान (24) के रूप में हुई है। उसे 12 फरवरी को पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में नोएडा लिंक रोड के पास से गिरफ्तार किया गया था।

डिवाइडर से टकराई मिनीवैन, पांच की मौत

मेहसाणा। गुजरात के उंडा-मेहसाणा राजमार्ग पर एक मिनीवैन के डिवाइडर से टकराने के बाद एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। हादसे में छह अन्य घायल हो गए। चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान रामलाल कुमावत, कोमल कुमावत, कैलाशभाई कुमावत और आयुष कुमावत (04) के रूप में हुई है।

डिजिटल दावा, सिस्टम हांफा, ऑनलाइन एफआईआर कराने पर हर जिले में 'एरर'

डिजिटल पारदर्शिता और ऑनलाइन सुगमता के दावों के बीच राज्य की ऑनलाइन एफआईआर व्यवस्था तकनीकी अड़चनों में उलझी रही।
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी सीसीटीएनएस के तहत शुरू की गई सुविधा के तहत टीम हरिभूमि ने एकाउंट बनाकर कई बार एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की लेकिन हर बार एरर ही बताया जाता रहा।

गिरौरी केशरवानी के साथ विकास चौबे रायपुर-बिलासपुर समेत सभी जिलों में ऐसी दिक्कत बताई जाती रही। रायपुर कमिश्नर संजीव शुक्ला ने कहा कि तकनीकी दिक्कत है, उसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। वहीं बिलासपुर एसपी ने कहा कि सर्वर ने काम करना आज ही शुरू किया है। कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सर्वर में पखवाड़े भर से परेशानी आ रही है। फरियादियों को थाने जाकर एफआईआर करानी पड़ रही है। हरिभूमि ने ॥ शेष पेज 5 पर

टीम हरिभूमि ने कई एकाउंट से एफआईआर की कोशिश की, हर बार एरर बताया

एरर और पुराने कानूनों को अपडेट करने में चुनौतियां
पुलिस अधिकारियों की मानते हैं कि स्थानीय ऑफलाइन सर्वर और केंद्रीय सर्वर के बीच डेटा सिंक न होने से जानकारी अपडेट होने में देरी होती है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर के धीमा होने और पोर्टल पर तकनीकी बाधाओं के कारण एफआईआर और अन्य रिकॉर्ड दर्ज करने में समय लगता है। इसके साथ ही पुलिस कर्मचारियों में सॉफ्टवेयर के संचालन को लेकर ॥ शेष पेज 5 पर

तकनीकी खामी के कारण
सीसीटीएनएस का वर्जन-2 लागू किया जा रहा है, इसलिए तकनीकी खामी के कारण सर्वर डाउन है। खामी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। समाधान एप में जल्द ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ लोग एफआईआर की स्थिति के बारे में जानकारी हरितल कर सकते हैं।
- डॉ. संजीव शुक्ला
पुलिस कमिश्नर रायपुर

सर्वर डाउन, कुछ परेशानी
सीसीटीएनएस पोर्टल और सॉफ्टवेयर में सर्वर डाउन होने और कुछ तकनीकी समस्या के कारण इसे शुरू करने में देरी हुई। अब इसे सुधार लिया गया है।
- पंकज कुमार पटेल, एडिशनल एसपी, बिलासपुर

यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने दिया आदेश

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज होगा केस

एजेंसी ॥ प्रयागराज अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बटुकों के साथ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए झूंसी पुलिस थाने के प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का शनिवार को आदेश दिया। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य द्वारा बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत दायर आवेदन पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने पिछले सप्ताह साक्ष्यों को देखने और पीड़ित बटुकों का बयान दर्ज करने के बाद फेसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ॥ शेष पेज 5 पर

मां का आशीर्वाद और अपार जनस्नेह

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 62वां जन्मदिवस उनके गृहवाम बगिया में अत्यंत उत्साह, आत्मीयता और पारिवारिक स्नेह के वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने गृहवाम बगिया स्थित अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी माता श्रीमती जसमनो देवी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा। जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी के स्नेह, शुभकामनाओं और आत्मीय स्वागत के लिए ॥ शेष पेज 5 पर

SIKSHA 'O' ANUSANDHAN SAAT-2026

Empowering students for a brighter future

B.TECH PROGRAMMES IN CORE COMPUTING

- Computer Science and Engineering
- Computer Science and Information Technology

APPROVAL & RECOGNITIONS

- Approved by UGC and AICTE
- Re-accredited by NAAC with A++ Grade
- Granted with Category-1 Graded Autonomy by UGC
- NBA Accredited Programmes

NIRF INDIA RANKINGS 2025

- 15th Best in University Category
- 22nd Best in Engineering Category

INTERNATIONAL RANKINGS 2026

- Ranked in QS World Rankings 2026
- Ranked in Times World Rankings 2026

To apply for admission through SAAT, Please visit: www.soa.ac.in

कार पोल से टकराई, दो सगे भाई सहित तीन की मौत, एक गंभीर

रायपुर/आरंग। राजधानी रायपुर से सटे रायपुर-महासमुंद मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाई सहित तीन युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा आरंग थाना क्षेत्र में कार पोल से टकराई। तेज रफ्तार टाटा विस्टा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर और लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए पोल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क हादसा में हर्ष कुमार देवांगन (21), उसका छोटा भाई राहुल देवांगन (20) तथा थानू सतनामी (22) की मौत हुई है। घायल की पहचान मिथिलेश धीवर (23) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार कार टाटा विस्टा सीजी-4 एचडी 2156 में चार लोग सवार थे। ॥ शेष पेज 5 पर

सबसे पहले लाइफ इश्योरेंस

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

सौ वर्षीय प्लान!

एलआईसी का जीवन उमंग

UIN No.: 512N312V03 PLAN NO.: 745
एक पार, नॉन-लिव्ड, व्यक्तिगत, बचत, आजीवन बीमा प्लान

अंतिम प्रीमियम के बाद से लेकर 99 वर्ष की आयु तक हर वर्ष पाइए मूल बीमाधन राशि का 8% के बराबर गारंटीड उच्चरजितीता लाभ और 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहने पर एकमुश्त परिपक्वता लाभ।

विशेषताएँ :

- आयु यो्यता : 30 दिन से लेकर 55 वर्ष तक
- न्यूनतम मूल बीमाकृत राशि : ₹ 2,00,000/-
- अधिकतम मूल बीमाकृत राशि : कोई सीमा नहीं
- प्रीमियम भुगतान अवधि : 15, 20, 25 एवं 30 वर्ष
- पॉलिसी अवधि : (100 में से प्रवेश पर आयु घटाकर) वर्ष

प्रमुख विशेषताएँ :

- 100 वर्ष की आयु तक आजीवन जोखिम बीमा-तुरक्षा
- पूरी प्रीमियम भुगतान अवधि में बोनस
- अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो)
- ऋण सुविधा

हमारा वॉट्सएप नं. **8976862090**

अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा एजेंट/नजदीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप **Hi**

कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827

एच वॉ कोलॉ कं. f y t i c LIC India Forever IRDAI Regn No.: 512

घोषघड़ी वाले फ्रोन कॉल्स तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें। आईआईसीआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश, राशियां लौटाना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या चंभामित ग्राहकों को ऐसे फ्रोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें। कृपया बिक्री के सम्पान से पहले बिक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें।

भारत का नजरिया एआई को कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित रखने के बजाय इसे आम आदमी की भाषा और जरूरतों के हिसाब से ढालकर एक डिजिटल क्रांति लाने का है। एआई अब हर क्षेत्र में गहराई से प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके साथ ही बड़े खतरे भी सामने आए हैं- नौकरियों पर असर और स्किल में बड़ा अंतर, डेटा प्राइवैसी और साइबर सुरक्षा, डीपफेक, गलत सूचना और चुनावी हस्तक्षेप भेदभाव और पक्षपात, इंसानी नियंत्रण से बाहर जाती टेक्नोलॉजी का डर। दूसरी एक बड़ी चिंता विदेशी एआई सिस्टम पर निर्भरता और उसके चलते मार्केट कंसंट्रेशन है। फिर भी, एआई अब केवल भविष्य की अवधारणा नहीं, बल्कि वर्तमान का हिस्सा बन चुका है। एआई लोगों को रोजगार देगा। 2025 में भारत में लगभग 2.9 लाख एआई से जुड़े रोजगार के अवसर पैदा हुए और 2026 में इसमें 32% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो करीब 3.8 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य दिखाता है। हालांकि एआई के लाभ तभी व्यापक होंगे, जब उसका उपयोग केवल बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों, छोटे उद्यमों और सामान्य नागरिकों तक पहुंचे। साथ ही, सरकार को इस बात पर भी निरंतर नजर रखनी होगी कि एआई का दुरुपयोग, जैसे फेक न्यूज, डीपफेक, साइबर अपराध और डेटा के अनैतिक इस्तेमाल समाज में अस्थिरता न पैदा करें। भरोसा और सुरक्षा, एआई के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं। *इन्हें हालातों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

एआई लोगों की मदद करेगा, रहना होगा अलर्ट



विश्लेषण

रवि शंकर

वरिष्ठ पत्रकार

भारत का नजरिया एआई को कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित रखने के बजाय इसे आम आदमी की भाषा और जरूरतों के हिसाब से ढालकर एक डिजिटल क्रांति लाने का है। एआई अब हर क्षेत्र में गहराई से प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके साथ ही बड़े खतरे भी सामने आए हैं। जैसे नौकरियों पर असर और स्किल में बड़ा अंतर, डेटा प्राइवैसी और साइबर सुरक्षा, डीपफेक, गलत सूचना और चुनावी हस्तक्षेप भेदभाव और पक्षपात, इंसानी नियंत्रण से बाहर जाती टेक्नोलॉजी का डर। इसलिए हमें एआई को लेकर अलर्ट भी रहना होगा।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जो कुछ हुआ, उसने साफ कर दिया कि यह केवल एक ग्लोबल इवेंट नहीं, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी सॉवरैनिटी का वैश्विक शंखनाद था, जिसकी गूँज पेरिस से लेकर न्यूयॉर्क तक सुनाई दी। इसमें शामिल दुनिया के दिग्गज नेताओं से लेकर टेक्नोलॉजी पर राज करने वाली कंपनियों के सीईओ तक ने जो बातें कहीं, वह भारत की चमक बयां करती हैं। इतना ही नहीं, भारत इस समिट के जरिए दुनिया को यह संदेश दिया है कि एआई का विकास सिर्फ ताकतवर देशों का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि यह ऐसा क्षेत्र बने जहाँ ग्लोबल साउथ की आवाज, जरूरतें और चुनौतियां भी केंद्र में हों। अब तक एआई पर वैश्विक बहस ज्यादातर अमेरिका, यूरोप और चीन के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन भारत जैसे देश के सामने विशाल आबादी, विज्ञानसाली अर्थव्यवस्था, डिजिटल डिवाइड, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विभिन्न भाषाएं और सामाजिक संरचना को लेकर अलग-अलग चुनौतियां हैं। भारत चाहता है कि एआई का इस्तेमाल केवल कॉर्पोरेट मनुष्य या सैन्य ताकत बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि यह गरीबी घटाने, सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और शासन को अधिक पारदर्शी बनाने का औजार बने। एआई समिट के जरिए भारत यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह एआई फॉर गुड का मॉडल पेश कर सकता है। वह डेमोक्रेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नंस का उदाहरण बन सकता है और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे में ला सकता है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और इस्तेमाल का ग्लोबल हब बनाने का बड़ा इतिहासिक फैसला किया है और सस्ती विज्ञान 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' पेश किया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से भारत में डिजाइन करने और दुनिया को डिलीवर करने का आह्वान किया। इस महत्वाकांक्षा को एआई समिट में भी प्रमुखता से दिखाया गया, जिसने भारत को ग्लोबल



साउथ में एक लीडर और दुनिया के मंच पर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर पेश किया। भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्रांति में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। वर्तमान में भले ही अमेरिका और चीन एआई के दो विपरीत ध्रुव बने हुए हैं, लेकिन भारत में एआई लीडर बनने की तीव्र आकांक्षा और क्षमता है। भारत में भी वर्तमान में एआई पर व्यापक शोध कार्य चल रहा है, जो वैश्विक समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है। एआई का उद्देश्य लोगों की मदद करना है, न कि उनकी जगह लेना। भविष्य में मनुष्य स्मार्ट सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे। सरकार की प्रतिबद्धता इंडिया एआई मिशन जैसी बड़ी पहलों से और मजबूत होती है, जिसके लिए अगले पांच सालों में 10,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसका मकसद कंप्यूटिंग पावर बढ़ाना और सस्ती दरों पर रिसर्च के मौके उपलब्ध करना है। दुनिया भर में एआई के क्षेत्र में भारत की तेजी से हुई तरक्की साफ दिखती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे अमेरिका और चीन के बाद एआई वाइब्रेंस में तीसरे स्थान पर रखा है। यह तरक्की भले ही गति दिखाती है, लेकिन

स्थापित एआई दिग्गजों से मुकाबले के लिए अभी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। अमेरिका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कंयूटिंग क्षमता और फाउंडेशन मॉडल डेवलपमेंट जैसे अहम क्षेत्रों में आगे है, जबकि चीन रिसर्च आउटपुट और पेटेंट जनरेशन में बाजी मारता है। भारत का एआई इकोसिस्टम अभी मैच्योर होने के बजाय तेजी से बढ़ रहा है। इस कंपीटिशन के माहौल में न सिर्फ एआई की बुनियादी क्षमताओं में बड़ा निवेश जरूरी है, बल्कि स्वदेशी विकास पर भी खास ध्यान देना होगा, खासकर सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, जहां भारत एक उपभोक्ता से निर्माता बनने की ओर बढ़ रहा है। आज जब दुनिया एआई क्रांति के मुहाने पर है और भारत इस क्षेत्र की तीसरी सबसे सक्षम शक्ति बनने की तैयारी कर रहा है इसी कारण दुनिया भर की नामी एआई कंपनियां देश में दिलचस्पी लेने के साथ भारी निवेश भी कर रही हैं, तब फिर सरकार को एआई क्रांति की चुनौतियों से सावधान रहने के साथ उससे उत्पन्न हो रहे अवसरों को भुनाने के लिए कोई ठोस रूपरेखा बनानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरत डेटा पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एआई टूल के पास जितना अधिक डेटा

होगा वो मॉडल उतना ही शक्तिशाली होगा। हालांकि, आधार और यूपीआई जैसी डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम तकनीक को कितने बड़े पैमाने पर लागू कर सकते हैं। अब यही काम हम एआई के साथ करने जा रहे हैं। भारत का नजरिया एआई को कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित रखने के बजाय इसे आम आदमी की भाषा और जरूरतों के हिसाब से ढालकर एक डिजिटल क्रांति लाने का है। एआई अब हर क्षेत्र में गहराई से प्रवेश कर चुका है। लेकिन इसके साथ ही बड़े खतरे भी सामने आए हैं- नौकरियों पर असर और स्किल में बड़ा अंतर, डेटा प्राइवैसी और साइबर सुरक्षा, डीपफेक, गलत सूचना और चुनावी हस्तक्षेप भेदभाव और पक्षपात, इंसानी नियंत्रण से बाहर जाती टेक्नोलॉजी का डर। दूसरी एक बड़ी चिंता विदेशी एआई सिस्टम पर निर्भरता और उसके चलते मार्केट कंसंट्रेशन है। फिर भी, एआई अब केवल भविष्य की अवधारणा नहीं, बल्कि वर्तमान का हिस्सा बन चुका है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत एआई को केवल तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि विकास, समावेशन और सुशासन के उपकरण के रूप में देख रहा है। तेजी से बढ़ती एआई प्रतिस्पर्धा के बीच यह विश्वास सम्लेन भारत के लिए अपनी उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखने का शानदार अवसर रहा है। एआई के लाभ तभी व्यापक होंगे, जब उसका उपयोग केवल बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों, छोटे उद्यमों और सामान्य नागरिकों तक पहुंचे। डिजिटल विभाजन को कम किए बिना एआई क्रांति अधूरी रहेगी। साथ ही, सरकार को इस बात पर भी निरंतर नजर रखनी होगी कि एआई का दुरुपयोग, जैसे फेक न्यूज, डीपफेक, साइबर अपराध और डेटा के अनैतिक इस्तेमाल समाज में अस्थिरता न पैदा करें। भरोसा और सुरक्षा, एआई के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं।

एआई छीनेगा नहीं, लाखों नौकरियां देगा युवाओं को



उम्मीद

विवेक शुक्ला

वरिष्ठ पत्रकार

आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की चर्चा है। राजधानी में एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा, सारे संसार से प्रतिनिधि भी भाग ले रहे थे। दरअसल, एआई तकनीक मशीनों को इंसानों जैसा सोचने-समझने की ताकत दे रही है। एआई आ रहा है। चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन। बैंक में एआई चैटबॉट्स, फेक्टरियों में रोबोट्स, गवर्नमेंट में ई-गवर्नंस। कुछ स्टूटन काम ऑटोमेट होंगे, लेकिन इतिहास बताता है कि नई तकनीक अंततः ज्यादा रोजगार पैदा करती है। विश्व आर्थिक मंद (डब्ल्यूईएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, एआई से नई रिक्रूटमेंट वाली नौकरियां बढ़ेंगी। एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर आदि। एनएसएसएससीओएम और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में एआई से 2025-2030 तक लाखों नई नौकरियां आएंगी। एआई टैलेंट की डिमांड 1 मिलियन से ज्यादा होगी, और एआई अपनाने से जीडीपी में 450-500 बिलियन डॉलर का इजाफा होगा। कई अध्येत्यों में प्रायः गया कि एआई से कुछ स्टूटन जोखिम बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन नई जॉब्स (जैसे एआई कॉन्ट्रोलर, एक्सपेरियेंस डिजाइनर) ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, व नए सेक्टर जैसे हेल्थटेक, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में अवसर खुलेंगे। एक बात साफ है कि आज के डिजिटल युग में एआई एक क्रांतिकारी तकनीक बन चुकी है। जहां कुछ लोग एआई को नौकरियों के लिए खतरा मानते हैं, वहीं वास्तविकता यह है कि भारत जैसे युवा-प्रधान देश में एआई नए और बेहतर रोजगार के द्वार खोल रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने एआई अपनाने में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत दुनिया में एआई प्रतिका की अती में सबसे आगे है, जहां सालाना अती दर लगभग 33% है। 2025 में भारत में लगभग 2.9 लाख एआई से जुड़े रोजगार के अवसर पैदा हुए और 2026 में इसमें 32% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो करीब 3.8 लाख नई नौकरियों का मतलब है। ये अवसर मुख्य रूप से मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई एप्लिकेशन जैसे क्षेत्रों में उभर रहे हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहर एआई जॉब्स के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर्स (जीसीपी) ने भी 2025 में करीब 4.5 लाख नई नौकरियां जोड़ीं, जिनमें एआई-संबंधित भूमिकाएं प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे नेताओं ने स्पष्ट किया है कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन्हें बदलकर नई संभावनाएं देगा। भारत-एआई मिशन, रिकल इंडिया और विभिन्न एडटेक प्लेटफॉर्मों के जरिए युवाओं को रीस्किलिंग और अप्सकिलिंग का अवसर मिल रहा है। एआई स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ा रहा है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लाखों सहायक रोजगार सृजित हो रहे हैं। एआई का नेट प्रभाव रोजगार पर सकारात्मक है। यह उत्पादकता बढ़ाता है, नए उद्योग खोल देता है और उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा करता है। भारत की 65% से अधिक युवा आबादी इय बढवाना का सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगी, बशर्ते हम कोशल विकास पर फोकस करें। कंप्यूटर की तरह, एआई भी जॉब किलर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर साबित होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही सेलेक्टिड एयरोस्पेस के साइंटिस्ट श्रेयांस जैन मानते हैं कि जो लोग एआई सीखेंगे, वे आगे बढ़ेंगे। नई रिक्रूटमेंट से बेहतर सैलरी, प्रमोशन और अवसर मिलेंगे। पर भारत में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लाखों लोग चिंतित हैं कि कहीं, एआई उनकी नौकरी तो नहीं छीन लेगा, लेकिन यह डर पुराना है। यह कौशल 1980-1990 के दशक को, जब कंप्यूटर भारत में आ रहे थे। तब भी यही डर था कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा। मजदूर युनिवर्सिटी पर उतरी, हड़तालें हुईं, विरोध प्रदर्शन हुए। सरकारों दबकतीं, बैंकों, रेलवे में हड़ जगह कंप्यूटर का विरोध। लेकिन कंप्यूटर ने भी रोजगार पैदा किए। संदेश साफ है एआई से नौकरियां नहीं छीनेंगी, बल्कि बढ़ेंगी बशर्ते हम इसे अपनाएँ, रिक्रूटमेंट अपोइड करें और आगे बढ़ें। सब मिलकर इस नई क्रांति का हिस्सा बनें।

भारत में एआई से 2025-2030 तक लाखों नई नौकरियां आएंगी। एआई टैलेंट की डिमांड 1 मिलियन से ज्यादा होगी और एआई अपनाने से जीडीपी में 450-500 बिलियन डॉलर का इजाफा होगा। इसलिए रिक्रूटमेंट अपोइड करें और आगे बढ़ें।

गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी पर निगरानी की जरूरत



चिंतन

योगेश कुमार

वरिष्ठ पत्रकार

दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। पूरी दुनिया से एआई के जानकार और अगुए हुए। इन्होंने एआई के बीच गेटेड नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से दिखाए गए एक रोबोट पर विवाद बंध गया है जो एक इन्टरनेशनल मुद्दा बन गया। मामला यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस रोबोट को खुद के द्वारा तैयार किया गया बताया था, लेकिन वह वो चीन का रोबोट निकला। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। यही नहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर मीडिया भी बन गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर देश ही नहीं दुनिया में भी चर्चा होने लगी है। स्थिति यह है कि एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से खुद का रोबोट बताकर चीनी प्रोडक्ट दिखाने के बाद बड़े स्तर पर किरकिरी हो गई। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बुधवार को भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट एक्सपोजे में अपना स्टॉल खाली तर्क कर दिया। बता दें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 'ओपिनियन' रोबोट एआई समिट में दिखाया गया जो एक रोबोटिक कुरता है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद इसकी सच्चाई संकेत सामने आई। लोगों ने रिसर्च किया और खोजकर पता चल गया। चीन प्रेस एक्सप्रेस हैटल से एक पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि भारतीय यूनिवर्सिटी ने चीन के रोबोट को खुद का रोबोट बताया। लेकिन खयाल यही है कि देशभर अपनी पहचान रखने वाली ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या इसके

पीछे कोई राजनितिक साजिश थी, क्योंकि इसके लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सरकार को बदनाम करने का भी काम हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अपनी बड़े स्तर पर उपस्थिति दर्ज करवाती थी और अपनी यूनिवर्सिटी को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया था। मामला यह है कुछ भी हो लेकिन इस घटनाक्रम से देश की साख पर बड़ा लगा गया। वहीं समिट में पहुंचे तमाम लोगों ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है यह बेहद निंदनीय है इससे न सिर्फ देश की बदनामी हुई है बल्कि यूनिवर्सिटी के प्रति लोगों में विश्वास खत्म हुआ है। स्थिति यह है कि देश के एआई भविष्य व गुणवत्ता पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो गए। इसके अलावा गलगोटिया यूनिवर्सिटी से सालाना हजारों विद्यार्थी पास आउट होते हैं और हाल ही में पढ़ रहे बच्चों को क्या कोई भी नौकरी देगा? इस घटना के बाद कई कंपनियों का दृष्टिकोण इस यूनिवर्सिटी के लिए बदल गया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में रोबोटिक्स अभी पूरी तरह विकसित नहीं रही है और इसे अभी एक विकसित हो रहे इकोसिस्टम के रूप में देखा जा रहा है लेकिन कुछ कंपनियों को खुश करने व अपने व्यापार को बढ़ाती करने में केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। बीते दो दशकों से रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे और आईआईटी मंडी ने रोबोटिक्स के एक प्रोफेसर ने कहा कि भारत के पास तकनीकी क्षमता और प्रतिभा होने के बावजूद इंडस्ट्रियल से जुड़ी चुनौतियां इस क्षेत्र की रफ्तार को सीमित कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 'एआई की आना का एक रोबोटिक शरीर खोजने जैसा है और यह एक कठिन क्षेत्र है क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग की लगभग हर शाखा के समन्वय की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जब वैश्विक एआई लीड में खुद को प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है ऐसे में यह घटना 'मेड इन इंडिया' की छवि के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। ऐसे में केन्द्र व राज्य सरकारों को मिलकर इस पर निगरानी रखनी की सख्त आवश्यकता है और इनकी देखरेख के लिए अलग से एक विभाग बनाना चाहिए जिससे की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न हो। सच्चाई यह है कि जो छोटे संस्थान होते हैं वहां बच्चों को अच्छे से शिक्षा जाता है। केवल बड़ी-बड़ी इमारतों को दिखाकर बच्चों के भविष्य के ज्ञान सिखाया किया जाता है। लेकिन अब गलगोटिया प्रकरण के बाद अब बड़े पश्चान ऑफ प्लान की जरूरत है।

रोजगार के साथ चुनौतियां भी बढ़ाएंगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता



चुनौती

चरणजीत चरण

वरिष्ठ साहित्यकार

जैसे ही हम एआई की बात करते हैं, इसे रोजगार के प्रति एक डर के रूप में देखा जाता है और युवाओं के लिए एक चुनौती माना जाता है। आज जैसा कि हम जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में इतना अधिक घुल-मिल गई है कि हम इसके बिना भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। जब हम इससे मिलने वाले लाभों की बात करते हैं, तो उससे होने वाले संभावित नुकसान स्वाभाविक रूप से हमारी चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। इसे लेकर सबसे बड़ा डर और भ्रम किसी भी देश या समाज में हो सकता है, वह है रोजगार में कटौती होना। इसमें कोई शक नहीं है कि एआई के माध्यम से बहुत से काम आसान हुए हैं, कार्यों में लगने वाले समय को न्यूनतम किया गया है तथा कार्य की सटीकता भी बढ़ी है; लेकिन यह चिंता भी चिंतन का विषय है कि यह तकनीक

रोजगार के लिए एक चुनौती बनकर उभरी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम की भौतिकवादी दुनिया एआई का इस्तेमाल किसी भी कार्य में सटीकता बढ़ाने और लागत कम करने में करती चाहती है। वहीं भारत की सोच इस विषय में बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, भारत इसका इस्तेमाल खुच में कटौती के रूप में नहीं, बल्कि गुणवत्ता में सुधार और मानवीय क्षमता के विस्तार के रूप में करना चाहता है। पश्चिम की दुनिया जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव क्षमताओं के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग करना चाहती है, वहीं भारत इसे मानव सहयोग के रूप में उपयोग करना चाहता है। हाल ही में हुए दिल्ली एआई समिट का मकसद भी यही है कि इसे न सिर्फ मानव सहयोगी के रूप में देखा जाए, बल्कि उसका इस्तेमाल कार्यकुशलता और सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए किया जाए। भारत और पश्चिम की दुनिया में शुरू से अब तक एक बुनियादी अंतर यही रहा है कि पश्चिम ने इस क्षेत्र में जितने भी नवाचार किए हैं, उन्हें बहुत गोपनीय रखा है। साथ ही, ऐसी किसी भी तकनीक को मानव श्रम की कटौती

के रूप में इस्तेमाल किया है और उनके तमाम प्रयोग भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके विपरीत, भारत का उद्देश्य ग्राामीय क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल कर स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने में अभूतपूर्व कार्य किया है। मरीजों का डेटा एकत्र करने से लेकर जटिल बीमारियों के निदान तक पहुंचना और छोटे-छोटे गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, इन सभी क्षेत्रों में भारत का कार्य सराहनीय है। यदि हम इसकी बुनियाद में जाएँ, तो देखते हैं कि इस प्रणाली के रखरखाव के लिए जिस बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, उसी से भविष्य में लाखों नए रोजगार सृजित होंगे। भारत में एआई को न सिर्फ सरकारी बल्कि अब निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। सरकार पूरी निष्ठा से इस दिशा में कार्य कर रही है कि इसका इस्तेमाल युवाओं में कौशल विकास के लिए हो, न कि छंटनी के लिए। भारत का 'इंडिया एआई मिशन' केवल शोध के लिए नहीं है, बल्कि सरकार की कोशिश है कि देश का युवा बुनियादी रूप से इस क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता और क्षमताओं का विकास करे। दिल्ली अंतर के अनुसार, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा समूह है। इसी डेटा का उपयोग करने के लिए जिस मानव संसाधन की आवश्यकता है, उसी के कारण

कई तरह की समस्याएं भी पैदा कर सकती है एआई



दृष्टिकोण

विकेश कुमार बडोला

स्वतंत्र संभारकर

नई दिल्ली के भारत मंडपम में जब 'इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, तब से एक स्वाभाविक प्रश्न द्वारा मन-मस्तिष्क आंदोलित हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं, कि क्या भारत व विश्व में प्राकृतिक कृषिकर्म एवं प्रकृति के समुचित संरक्षण हेतु भी कोई अधि मंथनपरक सम्मेलन कभी होगा? क्या इस दिशा में भारतीय शासन, विदेशी शासनों तथा देशी-विदेशी कंपनियों के अथाह धन-संसाधन धारी स्वामियों को इस बारे में कोई आत्मरति कभी होगी अथवा नहीं? जीवन की मुख्य आवश्यकताओं से पृथक एआई अर्थात् कृत्रिम मेधा का विषय सहसा इतना व्यापक व विशाल क्यों हो गया है कि यह चाहे-अनचाहे सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में आ गया है? ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि 'सॉफ्टवेयर कंपनियों, पूंजीपतियों तथा कम जनसंख्या के साथ अधिक तकनीक व प्रौद्योगिकी से समृद्ध विश्व के लघु आकार वाले देश एआई तकनीक बेचकर लाभार्जन करना चाहते हैं। इनमें अमेरिका प्रमुख है।

डेयरी उत्पादों पर किकर्तव्यविमूढ़ता के कारण भारत-अमेरिका के मध्य अपेक्षित व्यापार समझौता नहीं हुआ, तो भारतीय व अमेरिकी शासन तथा दोनों देशों के सॉफ्टवेयर कारोबारियों ने नवीनतम कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एआई के बलबूते पारस्परिक व्यापार में वृद्धि करने की नीति बनाई है। ये नीति अमेरिका में एआई के प्रसारण के बाद बृहद स्तर पर फैली आजीविका की समस्या तथा भारत में आगामी वर्षों में एआई के कारण संभवतः फैलने वाली आजीविका की समस्या की अनदेखी करके बनाई गई है। एआई न केवल आजीविका की समस्या अपितु सामाजिक, व्यक्तिगत, सार्वजनिक व आन्तव्यीय समस्याओं भी उत्पन्न करेगा। एक समय उदारराज्य के बाद वाहन उद्योगों को फलीभूत करने देशवासियों को झिपटिया, तिहािया और चौपटिया वाहन खरीदने, रखने व चलाने के लिए उकसाया गया था। आज उसके दुष्परिणाम सड़कों पर प्रतिदिन कई घंटों के जाम, समय की बर्बादी, सड़क चौड़ीकरण हेतु वन क्षेत्रों व प्राचीन वृक्षों के कटान, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक विकृतियों के स्वरूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। इन दुष्परिणामों का देश-दुनिया के शासन के पास कोई समाधान नहीं है। लोगों ने इनके साथ घुट-घुट कर जीने को नियति मान लिया है। इसी प्रकार की कब वस्तुओं, सुविधाओं व सेवाओं को रखने एवं खरीदने के लिए लोगों



चौरी-डकैती, साइबर ठगी, डीप फेक, घोखाधड़ी रोकने के लिए एआई के संबंध में त्वरित और कठोर दंड की नीतियां भी लागू करनी होंगी।

को विवश किया जाता रहा है। लोगों से कभी पूछा नहीं गया कि उन्हें ये सब कुछ चाहिए भी कि नहीं। लोगों के बीच यही स्थिति है एआई अर्थात् कृत्रिम मेधा की है। कंपनियों ने एक प्रौद्योगिकी विकसित कर दी है। अब उसे आभासी उत्पाद के रूप में बेचने के लिए

कई तरह की समस्याएं भी पैदा कर सकती है एआई

दुनिया के शासनों पर दबाव बनाओ कि अर्थात् शासकीय नीतियों के माध्यम से अपने देशों की जनसंख्या को इस उत्पाद के ग्राहक के रूप में परिवर्तित करने की योजनाएं बनाइए। एआई सम्मेलन का यही मूल उद्देश्य है। अमेरिका आधारित सॉफ्टवेयर की सर्वाधिक विशाल कंपनी गुगल, अपने आरंभिक सॉफ्टवेयर कर्म से लेकर नवीनतम एआई अनुप्रयोग को एक सूचनापरक आभासी उत्पाद बना, विश्व में प्रसारित कर अधिक से अधिक लाभार्जन करने हेतु व्यग्र है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या धारी देश है भारत। गुगल जैसी कंपनियों के लिए अपने सॉफ्टवेयर कारोबार को चमकाने के लिए, भारत न केवल ग्राहक संख्या के स्तर पर, अपितु भारतीय मूल के ग्राहकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के माध्यम से भी, एआई बाजार का केंद्र खिंदू बना हुआ है। एक अरब जनसंख्या के देश की जनसंख्या बहुत विशाल है। उसे एआई बेचा जाएना तो न केवल गुगल, बल्कि अमेरिका भी आर्थिक रूप से संपन्न बनेंगे। आजकल देखा जा रहा है कि भारतीय कृषिशेरो व युवाओं में व्यापक रुचि बने किनेट एआई के माध्यम से भी, एआई के संबंध में भी कितने ही सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नियम-कानून बन जायें, किंतु जब तक त्वरित व कठोर दंड की नीतियां लागू नहीं होंगी, तब तक कृत्रिम मेधा के माध्यम से भी कुछ भी यथोचित नहीं होगा। उद्देश्य जनकल्याण नहीं अपितु व्यक्तिगत व कंपनीगत लाभार्जन ही रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपवाद नहीं है। ये भी जनकल्याण नहीं, विशुद्ध लाभ की योजना है। कृत्रिम रूप में मेधा प्रस्तुत करनेवालों से सीधा प्रश्न है कि क्या यह मेधा बिना व्यक्ति के संचालित हो सकती है? अंततः इसे भी किसी व्यक्ति के मन-मस्तिष्क, विचारों-मानसों तथा हथों द्वारा ही तो चलाया जाना है। जब ऐसा है तो इस पर इतना अतिशयोक्तिपूर्ण मंथन क्यों किया जा रहा है? क्या देश-दुनिया में अभी तक प्रसारित डिजिटल व कम्प्यूटर आधारित लेन-देन, गतिविधियां तथा अन्य प्रसारण अनुप्रयोग प्रतिकूलताओं अर्थात् चोरी-डकैती, साइबर ठगी, डीप फेक, घोखाधड़ी, दुरूपचार, भ्रमिया सूचना तथा अन्य विमर्शियों से पूर्णतः मुक्त बाजार का केंद्र खिंदू बना हुआ है। एक अरब जनसंख्या के देश में एक देश-दुनिया में बेहोश, मक्कार, जशत, उपद्रवी, प्रकृति विरोधी, पंगे लेने की दुरूपचरियों से घिरे हुए तथा अन्य मानवीय दुर्भाव्यों से युक्त लोग रहेंगे, तब तब कृत्रिम मेधा हो अथवा कोई अन्य प्रौद्योगिकी, सभी का पूर्ण दुरुपयोग होता रहेगा। एआई के संबंध में भी कितने ही सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नियम-कानून बन जायें, किंतु जब तक त्वरित व कठोर दंड की नीतियां लागू नहीं होंगी, तब तक कृत्रिम मेधा के माध्यम से भी कुछ भी यथोचित नहीं होगा।

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

सुकमा में इस वर्ष 51 दिन में 12 नक्सलियों को किया गया ढेर

नक्सल प्रभावित जिलों की कहानी 2

फोर्स का प्रयास नक्सली समर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएं

राजेश दास ►► जगदलपुर

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में छह जिलों को नक्सल प्रभावित माना है। इनमें बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर शामिल हैं। इनमें से सुकमा में फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है और कई नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। बीते दो साल में 65 दुर्घटना नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस वर्ष बीते 51 दिन में ही 12 नक्सलियों को सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में हुए मुठभेड़ों में मार गिराने में फोर्स सफल रही है। अब सुकमा में केवल 13 हथियार बंद नक्सली बचे हैं। इनमें डीवीसी मेंबर राजे समेत निचले कैडर



►►शेष पेज 5 पर

सुकमा में उखड़ रहे पैर, डीवीसी राजे समेत 13 नक्सली बचे, फोर्स ने कहा-सरेंडर करो या मरो

आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली

सरकार के नक्सलवाद के खत्म के डेड-लाइन जारी होने के बाद आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वर्ष 2024 में 326, 2025 में 273 तथा वर्ष 2026 में 102 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। वर्ष 2024 से आज पर्यंत तक नक्सलियों से मुठभेड़ों व गिरफ्तारी के दौरान 186 अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। इन वर्षों में नक्सलियों के सबसे घातक हथियार माने जाने वाले कमांड व प्रेशर आईईडी की संख्या 141 है, जो नक्सल अभियान के दौरान बरामद किया जा चुका है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान नक्सलियों को बहादुरी से मुकाबला करते हुए वर्ष 2024 से अब तक सात जवानों की शहादत हुई है।



मार्च तक खत्म करने का संकल्प

मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प की प्राप्ति करने सातों जिलों में समन्वित और बहुस्तरीय कार्ययोजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में लक्षित रणनीतिक अभियान संचालित किए जा रहे हैं। जनता के सहयोग, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और प्रशासन की दृढ़ प्रतिबद्धता के बल पर बस्तर शीघ्र ही पूर्ण शांति, सुरक्षा और सतत विकास का सशक्त उदाहरण बनकर उभरेगा और बस्तर व छग से जल्द ही नक्सलवाद का खाम्ता कर दिया जाएगा।

—सुरेशराज पट्टनयन, आईजी बस्तर

शाह बोले-31 मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा नक्सलवाद

गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित 31 मार्च की समयसीमा तक देश से नक्सलवाद का खाम्ता कर दिया जाएगा।



पूर्वोक्त में पहली बार आरोपित 87वीं सीआरपीएफ दिवस परेड को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां पथरबाजी की घटनाओं की संख्या घटकर शून्य हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मणिपुर में जातीय हिंसा से निपटने और केवल तीन वर्षों में माओवादियों को कम्मर तोड़ने के लिए भी सीआरपीएफ को तैनात किया गया। उन्होंने कहा, मैं सीआरपीएफ पर भरोसा कर सकता हूँ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सल समस्या का सफाया कर देंगे।

छत्तीसगढ़ की प्रशंसा की

गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करंटिंग पहड़ियों में 21 दिनों के ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' को तैनात किया गया। उन्होंने कहा, मैं सीआरपीएफ पर भरोसा कर सकता हूँ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सल समस्या का सफाया कर देंगे।

►►शेष पेज 5 पर

ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराया

भारतीय बेटियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, टी-20जीती सीरीज



हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 17 रन से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय महिला टीम ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टीम इंडिया ने पहली बार टी20 सीरीज जीती है। शनिवार को एडिलेड में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने स्मृति मंधाना (82) और जेमिमा रोड्रिग्स (59) की अर्धशतकीय प्रारियों की मदद से 20 ओवर में छह विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित ओवरों में नौ विकेट खोकर सिर्फ 159 रन ही बना सकी। इस ►►शेष पेज 5 पर

मंधाना ने ताबड़तोड़ 82 रन की पारी खेली

टीम इंडिया की तरफ से स्मृति मंधाना ने 82 रन की धुआंधार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 55 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 82 रन बनाए। हालांकि, वो शतक से चूक गईं।

रोड्रिग्स ने खेलेली अर्धशतकीय पारी

स्मृति मंधाना के अलावा, इस मैच में जेमिमा रोड्रिग्स ने भी 59 रन की अहम पारी खेली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 177 का लक्ष्य दिया। स्मृति और जेमिमा के बीच 121 रन की तगड़ी साझेदारी भी हुई। जेमिमा ने 46 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके की मदद से 59 रन बनाए।

छत्तीसगढ़ में 25 लाख वोटर घटे, रायपुर में सबसे ज्यादा, खैरागढ़ में सबसे कम नाम कटे

छत्तीसगढ़ में अब कुल वोटर... 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914, पहले थे 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 थी। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 हो गई। दावा-आपत्तियों की सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्वाचक नामावली जारी की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई। अंतिम चरण में सुनवाई के बाद 2 लाख 34 हजार 994 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि करीब 24 लाख 99 हजार से अधिक नाम सूची से विलोपित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी या दोहराव वाले नाम हटाकर सूची को शुद्ध किया गया। अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 1,87,30,914 रह गई है। उन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए नागरिकों का आभार जताया।

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है, जिसमें प्रदेश में करीब 24 लाख 99 हजार 823 वोटरों के नाम कटे हैं। सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 4 लाख 98 हजार 556 वोटरों के नाम काटे गए हैं। वहीं सबसे कम खैरागढ़ में 9,843 मतदाताओं के नाम कटे हैं। प्रदेश में अब कुल वोटरों की संख्या 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई है।

मतदाता सूची में नाम नहीं है तो करें ये काम

यदि आपका नाम अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर उसके साथ घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।



रायपुर टॉप पर सुकमा में सबसे कम वोटर

वर्ष 2026 की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या के मामले में रायपुर जिला शीर्ष पर है, जबकि सुकमा सबसे नीचे है। आंकड़े बताते हैं कि शहरी और अर्ध-शहरी जिलों में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, वहीं बस्तर अंचल और नवगठित जिलों में मतदाता संख्या कम बनी हुई है। यह वितरण प्रदेश की जनसंख्या संरचना और क्षेत्रीय संतुलन को स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है।

पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर

निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस अभियान से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है, जिससे आगामी चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, ताकि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिल सके और फर्जी नामों पर रोक लगे।

आप के जिले में मतदाता

रायपुर	1393967
बिलासपुर	1341254
दुर्ग	1135061
रायगढ़	842695
बलौदाबाजार-भाटापारा	840661
कोरबा	818010
महसूमद	796873
राजनांदगांव	792482
बेमतरा	725023
सुरजपुर	675186
सैत	670283
बालोद	656301
जांजगीर-चांपा	645105
जशपुर	622084
कबीरगंज	607917
धमतरा	606042
सरगुजा	602310
सारंगढ़-खिलाईगढ़	536343
उत्तर बस्तर कांकेर	540273
बस्तर (जगदलपुर)	520392
मुंगेली	446306
गिरियाबंद	437624
बलरामपुर	418340
कोडगुम	379213
मन्डलाद-चिरमिरी-भरतपुर	292599
खैरागढ़-छुईखन-गोई	216900
गैरेना-पेड़ा-मरवाही	188855
नारायणपुर	181736
दक्षिण बस्तर दंतवाड़ा	172864
कोरिया	159816
मोहन-मणपुर-अंबागढ़ चौकी	158680
बीजापुर	155180
सुकमा	154539

inh
छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल देखें
TATA PLAY **airtel**
चैनल नं. 1155 चैनल नं. 366

खबर संक्षेप
आरोपी डिप्टी कलेक्टर उड़के निलंबित
बालोद। डौंडी क्षेत्र की एक युवती की शिकायत पर राज्य शासन ने डिप्टी कलेक्टर दिलीप उड़के को निलंबित कर दिया है। अधिकारी पर शायी का झांसा देकर यौन शोषण करने और लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोंडिता ने बताया कि वर्ष 2017 में दोनों की पहचान पढ़ाई के दौरान हुई थी। आरोप है कि दिलीप उड़के ने शायी का वादा कर संबंध बनाए। युवती का कहना है कि उसने ►►शेष पेज 5 पर

बस और वैन की टक्कर में चार की मौत
भोपाल। मध्यप्रदेश के भिंड जिले में शुक्रवार देर रात को राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार बस के वैन से टकरा जाने से चार लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। यह हादसा तड़के करीब ढाई बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिमका गांव के पास हुआ। यह स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। गोहद चौराहा के थाना प्रभारी (एसएचओ) मनीष धाकड़ ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि खाली बस ने वैन को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार चार लोगों की मौत पर ही मौत हो गई।

ट्रंप के शुल्क आदेश रद्द होने के बाद भारत पर ऐसा असर
भारत पर 18 नहीं, लगेगा 10 प्रतिशत ही टैरिफ!
हरिभूमि न्यूज ►► नयी दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापक शुल्क आदेशों को उच्चतम न्यायालय की तरफ से रद्द कर दिए जाने के बाद अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर नया वैश्विक शुल्क लगाने की घोषणा की है जिसके तहत भारत को अब पहले के 25 प्रतिशत के बजाय केवल 10 प्रतिशत के जवाबी सीमा शुल्क का ही सामना करना होगा।



भारत रहा सबसे बड़ा साझेदार
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। 2021 से 2025 के दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 186 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें भारत के पक्ष में 41 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा। सेवाओं के क्षेत्र में भारत ने 28.7 अरब डॉलर का निर्यात किया और 25.5 अरब डॉलर का आयात किया, जिससे 3.2 अरब डॉलर का अतिरिक्त लाभ हुआ।

भारत ने तोड़ी चुप्पी, कहा-कर रहे अध्ययन
भारत सरकार ने हम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के डेवलपमेंट और इसके असर पर भारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारतीय सरकार अमेरिकी टैरिफ और उनके प्रभावों से संबंधित घटनाक्रमों को स्टडी कर रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र इस फैसले की जांच करेगा और वाणिज्य मंत्रालय या विदेश मंत्रालय में से कोई एक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देगा।

सुपर-8 : बारिश के कारण रद्द
न्यूजीलैंड-पाकिस्तान का मुकाबला, बटे 1-1 अंक

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप का पहला सुपर-8 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। शनिवार को इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन बारिश के चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। इस मैच के रद्द होने के बाद दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटे गए हैं। अब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 24 फरवरी को मुकाबले में उतरेगी, जिसके बाद पाकिस्तान का सामना 28 फरवरी को श्रीलंका से होगा।

एसीबी की बड़ी कार्रवाई
घर में 90 हजार घूस लेते पकड़ा गया फूड इंस्पेक्टर
हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मस्ती के फूड इंस्पेक्टर को राशन दुकान आवंटन आबंटन आदेश जारी करवाने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत मांग की। बाद में उनके बीच 90 हजार रुपए में सौदा तय हो गया। श्री पटेल रिश्वत नहीं देना चाहते थे, बल्कि फूड इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ाकर सबक सिखाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन के बाद 21 फरवरी को ट्रेप की योजना बनाई गई। फूड इंस्पेक्टर वख्रकार ने श्री पटेल को रिश्वत की रकम 90 हजार रुपए लेकर अपने महावीर सिटी के घर में बुलाया था। एसीबी की टीम उसके घर के पास तैनात हो गई थी। श्री पटेल ने घर में जाकर फूड इंस्पेक्टर ►►शेष पेज 5 पर



दूसरी बार कराई थी पोस्टिंग
फूड इंस्पेक्टर वख्रकार पूर्व में मस्ती एसीडीएम कार्यालय में पदस्थ थे। रिश्वत लेने की शिकायत पर उन्हें वहां से हटाकर खाद्य शाखा जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से मस्ती में पोस्टिंग करा ली।

23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा सदन, 15 बैठकें होंगी
विधानसभा बजट सत्र कल से, कवासी लखमा सदन में रहेंगे सशर्त उपस्थित
हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा, इस दौरान 15 बैठक प्रस्तावित हैं। बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि शराब घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा जमानत पर रिहा हो गए हैं, उन्होंने 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से लिखित बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी है। शर्तों के मुताबिक कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र विधानसभा में उपस्थित रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बताया कि महाधिवक्ता क छत्तीसगढ़ के अभिमत अनुसार कवासी लखमा विधानसभा सदस्य को कुछ शर्तों के आधार पर विधानसभा के फरवरी ►►शेष पेज 5 पर

Amul Milk. Always Fresh.
Amul Taaza
180 days shelf life
No need to boil
Anytime, anywhere

कुछ साल पहले तक वर्क फ्रॉम होम के बारे में कम ही लोग जानते थे। लेकिन आज कंडीशन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर वर्क फ्रॉम एनीवेयर तक पहुंच चुकी है। कई सर्विस सेक्टर ऐसे हैं, जिसमें यह वर्क मोड खूब पॉपुलर हो चुका है। इस मोड के अनेक फायदे हैं तो कुछ कमियां भी हैं। इन सबके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे।

कहीं से भी काम करने की आजादी वर्क फ्रॉम एनीवेयर



कवर स्टोरी / कीर्तिशेखर

करीब पांच वर्ष पहले कोरोना महामारी ने कार्यशैली में जिस बदलाव को मजबूरी में शुरू कराया था, वह अब स्थायी जीवनशैली का विकल्प बनता जा रहा है। पहले सवाल था- क्या घर से काम करना संभव है? अब सवाल बदल चुका है- क्यों न कहीं से भी काम किया जाए? इसी सवाल से जन्म होता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर की अवधारणा का यानी, ऐसा काम जिसे करने के लिए न तो ऑफिस की दीवारें जरूरी हैं, न किसी तय शहर की सीमा, बस आपका अपना लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्शन हो और थोड़ी-सी मानसिक एकाग्रता, इसके बाद कहीं पर भी आप अपना ऑफिस वर्क शुरू कर सकते हैं।

ऐसे बदलती गई कार्यशैली: वर्क फ्रॉम होम ने लोगों को यह सिखाया कि जरूरी नहीं कि हर काम मीटिंग रूम या ऑफिस डेस्क पर ही बैठकर किया जाए। इस अवधारणा ने यह भी बताया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब केवल कुर्सी पर बैठना नहीं होता। आउटपुट ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद लोगों ने महसूस किया कि अगर घर से काम करना संभव है, तो फिर इंटरनेट की बदौलत कहीं से भी काम करना संभव है। कोरोना और उसके बाद से ही लोगों ने घूमने गए हिल स्टेशनों, समुद्र किनारे या शहर से अपने गांव जाकर घर के एक कोने में बैठकर देश-विदेश की मल्टीनेशनल कंपनियों का काम करने लगे। यहीं से वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट व्यवहार में उतरा।

इसलिए चुन रहे यह तरीका: वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने की कई वजहें हैं। महानगरों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। भारी-भरकम किराए के बाद ही किराए का मकान मिलता है, बल्कि वहां जिनगी भी बहुत मुश्किल भरी हो जाती है। ऑफिस आने-जाने में रोज ट्राफिक जाम से पाला पड़ता है। परिवार साथ न होने की वजह से खाने की समस्या होती है। घर और परिवार से दूर रहने के कारण हर समय मानसिक अशांति रहती है। इस तरह काम तो होता है, पर जीवन बेचैन रहता है। इसलिए युवाओं का कहना है कि अब वो जीवन के लिए काम करना चाहते हैं, काम के लिए जीवन की हायतीबा नहीं झेलना

चाहते। नतीजा यह है कि नई पीढ़ी के बहुत से लोग वर्क फ्रॉम एनीवेयर का विकल्प बड़ी सहजता से चुन रहे हैं, क्योंकि यह विकल्प उन्हें भरपूर आजादी का एहसास कराता है। इस कॉन्सेप्ट का मेन टारगेट: वर्क फ्रॉम एनीवेयर के बारे में इस बात को समझना जरूरी है कि इसका मतलब डिजिटल घुमकड़नी नहीं है, न ही इसका मतलब है कि कहीं भी घूमते-फिरते रहें और जब मौका मिले या मन करे तो काम कर लें। अगर इस धारणा का मतलब यह हो जाएगा, तब तो काम करना प्राथमिकता नहीं रह जाएगा। प्रोफेशनल्स के लिए उनका वर्क बहुत मायने रखता है। ऐसे में इंटरनेट ने बौद्धिक काम करने वाले लोगों को यह सुविधा तो दी ही है कि अगर हिल स्टेशन पर घूमने जाएं, तो समय निकालकर वहां से भी अपना काम कर सकें। मां-बाप के पास गांव जाएं तो वहां भी साथ अपना काम लेकर जाएं और कहीं किसी जरूरी यात्रा पर निकल रहे हों तो भी अपना काम अपने साथ रख सकते हैं।

इन फायदों में है सफल यह मॉडल: वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट सर्विस सेक्टर में ही संभव है कि आप कहीं से भी अपनी विशेषज्ञता संबंधी सेवाएं अपने नियोक्ता को दे सकें। हर काम वर्क फ्रॉम एनीवेयर के ढांचे में फिट नहीं होता है। बहरहाल, जो काम इस मोड में सही से किए जा सकते हैं, वो क्षेत्र हैं- आईटी और सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, ऑनलाइन टैलिंग, कस्टमर सपोर्ट-कंसल्टेंसी, एचआर असिस्टेंस और फाइनेंस एनालिसिस भी इस वर्क पैटर्न से संभव है। दूसरे शब्दों में जिन कामों में फिजिकल उपस्थिति या मशीनरी को मौजूदगी की जरूरत नहीं होती, उन क्षेत्रों में यह मॉडल तेजी से अपनाया जा रहा है। एप्लॉई-एप्लॉयमेंट दोनों खुश: कंपनियां इसलिए इस मॉडल को स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि इससे उनको भी फायदा है। इससे

उन्हें ऑफिस स्पेस पर खर्च नहीं करना पड़ता। ऑफिस चलाने के लिए जो एस्टेटिजिमेंट खर्च होते हैं, उनसे भी बचाव हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को भर्ती करने के लिए पूरी दुनिया का दायरा मिल जाता है। कर्मचारी भी इससे संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हर रोज घर से काम करने के लिए नहीं निकलना पड़ता और न ही यात्रा करने की जो परेशानियां और तनाव होती हैं, उनसे निपटना पड़ता है। कंपनियां भी अब इस बात को समझ चुकी हैं कि अगर सल्लुयिटी के बीच कर्मचारी को काम करने का मौका मिलता है तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। इसलिए वे ऐसे कर्मचारियों को रखना पसंद करती हैं। इससे कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उनके रहने और दूसरी जगह पर जाकर खाने-पीने की जो भारी भरकम लागत आती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। घर से ऑफिस तक जाने में जो समय लगता है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। यह बचा हुआ समय व्यक्तिगत रुचियों का आनंद लेने और आराम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कह सकते हैं इस अवधारणा से काम कराने वाला भी खुश होता है और काम करने वाला भी खुश और दोनों को फायदा होता है।

प्रोफेशनल्स का बचता है टाइम: काम की इस अवधारणा का एक फायदा यह है कि लोग दिन में ऑफिस का काम करते हैं और फिर जो उनका दफ्तर तक जाने और आने का समय बचता है। उस समय का उपयोग बागवानी करने, संगीत सीखने, लेखन करने या अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए लगाते हैं। मौजूद है कुछ चुनौतियां: इस वर्क मोड में सबसे पहली चुनौती तो यह है कि ये काम वही हो सकता है, जहां इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो, बिजली की आपूर्ति चौबीसों घंटे और काम करने के लिए एक सुरक्षित और एकांत जगह हो। साथ ही वहां दफ्तर जैसा माहौल बनाने की सुविधा हो। इसके अलावा सेफ्टि डिस्प्लिनी भी जरूरी होता है। कुछ लोग जब खुद निर्णय लेना होता है, तो कंसटेंट होकर काम नहीं करते। ऐसे काम करने के तरीके से कई प्रोफेशनल्स का निजी जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। वे ऑफिस वर्क में बहुत समय देने लगते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग शुरू-शुरू में यह फॉर्मूला अपनाते हैं, लेकिन जल्द ही ऊब कर ऑफिस आने लगते हैं। क्योंकि घर में काम करते हुए उनके वर्किंग आवर बहुत बढ़ जाते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर करते समय भले तनाव कम होता हो, आजादी खूब महसूस होती हो, लेकिन सामाजिक संपर्क से कट जाते हैं और अकेलेपन की आशंका से घिर जाते हैं। इसलिए कई बार कहीं से भी काम करने की सुविधा का नुकसान मानसिक रूप से बीमार होने के रूप में सामने आता है। इसलिए लोग अब हाइब्रिड मॉडल को बेहतर मान रहे हैं यानी चार दिन घर में और दो दिन दफ्तर में काम करना, सही संतुलन है। न, महिलाओं को जरूर काम करने की इस शैली का फायदा मिलता है, क्योंकि इसके चलते उन्हें होम मैकिंग और करियर में संतुलन बनाने में मदद मिलती है। *

आज के दौर में जीवन को सुविधाजनक बनाने वाला मोबाइल बेसुमार लोगों को अपना लती भी बना रहा है। इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए अब लोग तरह-तरह के उपाय आजमा रहे हैं। इनके बारे में आप भी जानिए।



मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए आजमाए जा रहे तरह-तरह के उपाय

टेक्नोलाइफ लोकमित्र गौतम

हर सुबह आंख खुलते ही मोबाइल। रात में सोते समय आखिरी नजर तक मोबाइल। दिन में बीच-बीच में सैकड़ों बार स्क्रीन चेक करना। अब ये किसी व्यक्ति विशेष की आदत नहीं बल्कि ज्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल बन गई है। अब मोबाइल में नोटिफिकेशन देखा याद नहीं रहना पड़ता। लोगों की यह स्वतः आदत बन गई है। लेकिन इसी दौर में कुछ और भी दिलचस्प और विरोधाभासी बातें भी हो रही हैं। एक ट्रेंड बहुत तेजी से उभर रहा है और यह है मोबाइल से दूरी बनाने का। नहीं, लोग तकनीक छोड़ नहीं रहे बल्कि उसके साथ नई-नई शक्तों के तहत रिसर्चा तय कर रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन बंद कर रहा है, कोई फोन ग्रे स्कैल पर डाल रहा है, कोई डंब फोन खरीद रहा है, तो कोई रिवार को मोबाइल अलमारा में बंद करके उसमें ताला लगा देता है। मोबाइल को लेकर उसके पक्ष और उसके विरोध में एक से बढ़कर एक आदतें दुनिया का ध्यान खींच रही हैं।

स्क्रीन अनलॉक करते थे, वही ऊपर बताए गए उपाय यानी नोटिफिकेशन मिनिमलिज्म के बाद अब ये संख्या घटकर 40 से 50 बार रह गई है। ग्रे स्कैल मोड: इसका मतलब है फोन की रंगीन स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट में बदल देना। फोन की दुनिया काली-सफेद होते ही लोगों का रोल्लस में आकर्षण घट जाता है और स्कॉल करने का मन ही नहीं रह जाता। यह एक छोटा-सा उपाय है, लेकिन इसके बेहद असरदार मनोवैज्ञानिक नतीजे हासिल होते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग अपने फोन में डाउनलोड किए गए हर मीडिया एप के लिए दिन में 20 से 30 मिनट की लिमिट तय कर देते हैं और लिमिट खत्म होते ही यह एप अपने आप ही लॉक हो जाते हैं, जिससे इनसे मुक्ति मिल जाती है। ये उपाय शुरू में तो झुंझुलाहट पैदा करता है, मगर 3-4 दिन के बाद इसकी आदत बन जाती है।

फोन मुक्त दिन की शुरुआत: कुछ लोग इन दिनों सुबह जगने के बाद एक से दो घंटा तक बिस्कुल फ्री रहना चाहते हैं, जिससे इनसे मुक्ति मिल जाती है। ये उपाय शुरू में तो झुंझुलाहट पैदा करता है, मगर 3-4 दिन के बाद इसकी आदत बन जाती है।



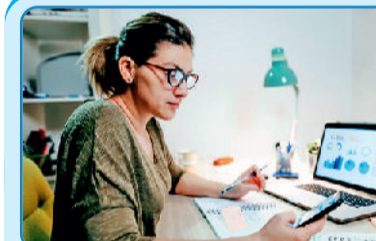
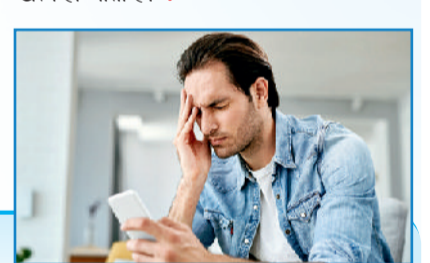
स्विच ऑफ रहता है, वे फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, एक्सरसाइज का अपना रूटीन खत्म करते हैं या ऐसा कुछ नहीं भी करते हैं तो इस दौरान सिर्फ खिड़की या बालकनी से बाहर झांकेते हैं। सोशल मीडिया फारिस्टिंग: कुछ लोग सोशल मीडिया फारिस्टिंग का उपाय भी आजमा रहे हैं। फोन से दूर रहना का वह एक और उपाय है। इसके चलते जैसे कुछ लोग धार्मिक रूप से हफ्ते में किसी एक या दो दिन उपवास रखते हैं। लगभग उसी तरह इस प्रयोग के तहत लोग हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन फोन से पूरी तरह से दूर रहने का उपाय आजमाते हैं। बेडरूम से बाहर फोन: कुछ लोग अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखकर सोते हैं। इस तरह फोन को बेडरूम से बाहर रखने के बहुत फायदे मिलते हैं। इससे नींद बेहतर आने लगती है। रात की स्कॉलिंग खत्म हो जाती है। *

क्यों छोड़ना चाहते हैं फोन: हाल के कुछ सालों में ऐसे कई अनुभव सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि मोबाइल लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता देता है। यह भी महसूस किया गया है कि लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करने से अधूरेपन का एहसास बढ़ जाता है। मोबाइल की लत लग जाए, तो कब देखते ही देखते टाइम फुर् हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इन सबके अलावा हाल के सालों में बिना कुछ किए लोगों को एक ऐसी थकान जकड़ रही है, जो जानकारों के मुताबिक मोबाइल की देन है। ऐसे ही और भी अनेक कारण हैं, जिसके चलते अब लोग मोबाइल से अलग पूरी तरह से नहीं, तो बीच-बीच में कुछ समय तक के लिए पिंड छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए इन दिनों लोग मोबाइल से दूर रहने के लिए तरह-तरह के उपाय आजमा रहे हैं। इनमें से कुछ के बारे में बता रहे हैं।

नोटिफिकेशन मिनिमलिज्म: बहुत से लोग अब सिर्फ कॉल और जरूरी एप के नोटिफिकेशन ही चालू रखते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया लाइक और ई-मेल अलर्ट, सब कुछ लोग बंद कर रहे हैं। इस कारण फोन हाथ में लेने की अपन आप जरूरत कम रह जाती है। ऐसे उपाय अपनाने वाले लोग बताते हैं- जहां वह पहले 125 से 150 बार तक

मानसिक स्वास्थ्य के लिए है जरूरी

लोग इस बात को गंभीरता से समझने लगे हैं कि फोन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल के कारण उनकी आंखों पर ही नहीं, ध्यान लगाने की क्षमता पर, भावनात्मक स्थिरता पर और यहां तक कि आत्मसंतोष की अनुभूति पर भी जबर्दस्त असर पड़ने लगा है। मोबाइल से दूर रहना एक तरह से खुद के पास होने जैसा है। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अनुभव बताते हैं कि वो खिलना ही ज्यादा फोन में रहते हैं, उनका ही ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे में इससे दूरी बनाने की आदत मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाती है।



वर्क फ्रॉम एनीवेयर के लिए जरूरी सुविधाएं

- घर में तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है।
- घर में लैपटॉप के साथ बैकअप पावर की सुविधा होना जरूरी है।
- घर में काम करने के लिए ऑफिस जैसे स्थान का होना जरूरी है।
- रोज सुबह अनुशासित ढंग से तैयार होकर दफ्तर की तरह काम करना जरूरी है।
- घर से काम करते समय कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान भी जरूरी है। अगर कंप्यूटर की बैकअप समझ नहीं है तो कभी-भी अगर लैपटॉप या वर्क स्टेशन में कोई समस्या आ गई, तो तब तक काम नहीं कर पाएंगे, जब तक घर कोई मैकेनिक आकर समस्या हल न करे।
- घर से काम करते समय लगातार उत्साह बनाए रखना भी जरूरी है ताकि अपना नियमित रूटीन सही से पूरा कर सकें।



गजल हबीब कैफी

मोहब्बत में जो लिखता है
अंधेरे में भी दिखता है

वहां कुछ फूल खिलते हैं
जहां वो पांव टिकता है

जिसे सब इश्क कहते हैं
सर-ए-बाजार बिकता है

फकत रोटी नहीं सिकती
तवे पर दिल भी सिकता है

महकता फूल लिखना था
उसी को खार लिखता है

व्यंग्य महेश कुमार केशरी

कहते हैं, सांप चंदन के पेड़ से हमेशा लिपटते रहते हैं। हालांकि मैं चंदन जैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ, फिर भी न जाने क्यों आस-पड़ोस के लोग मुझसे लिपटने को आतुर रहते हैं। कुछ ऐसे ही बगल के घर में रहने वाले मेरे एक पड़ोसी भी हैं। मेरे घर आ धमकने का उनको बस बहाना चाहिए। कभी चीनी, कभी टमाटर, कभी धनिया पत्ती तो कभी मिर्च गोलकी मांगने चले आते हैं। उन पड़ोसी महाशय को जब-जब कोई जरूरत होती है, वे भुजंग की तरह मुझसे आकर चिपट जाते हैं। गोया कि मैं आदमी नहीं बल्कि चंदन का पेड़ हूँ। उनका मेरे घर आना-जाना ऐसे होता है, जैसे मेरा घर नहीं, कोई धर्मशाला हो। ऐसे पड़ोसी मुझे मिले हैं, जिनको दिन भर में मुझसे दसियों बार काम पड़ता है। 'भाई साहब! भाई साहब!' कह-कह कर वे मुझे चुना लगाते रहते हैं। कभी-कभी तो मुझे लगता है, जैसे मैंने इन पड़ोसी महाशय को गोद लिया हुआ है। और वे मेरे बच्चे सरीखे हैं। वाह रे भाई! मान-न-मान मैं तेरा मेहमान। कभी 'हम बाहर जा

मेरे घर आ धमकने का पड़ोसी महोदय को बस बहाना चाहिए। कभी चीनी, कभी टमाटर, कभी धनिया पत्ती तो कभी मिर्च गोलकी मांगने चले आते हैं। गोया मेरा घर नहीं, कोई धर्मशाला हो।

प्रभु बचाए ऐसे पड़ोसी से



द्वारा गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए फैज, करीब चार वर्ष तक जेल में रहे। इस दौरान फैज और पुलिस के बीच हुई खत-ओ-किताबत का महत्व किसी ऐतिहासिक दस्तावेज से कम नहीं है। यहां गौर करने वाली बात है कि फैज की गिरफ्तारी ने उन्हें बेबस नहीं और मजबूत बना दिया था। 17 जुलाई 1952 को लिखे खत में वह कहते हैं, 'यह जख्म बहुत अचानक, बहुत बेसबब लगा है लेकिन इसे सहने का बल मुझमें है। और इसके सामने भी मेरा खिस नहीं झुकेगा।' 24 अगस्त 1954 को पुलिस, फैज को लिखे खत में भीगे जज्बातों से उनकी गैरमौजूदगी को महसूस करती है, 'जब मीजू ने केक काटा, उसने अपना मुंह बना लिया। आंखें बंद कीं और उस चीज की दुआ मांगी, जिसके लिए हम सब मांग रहे थे- खुदा तुम्हें हमारे पास घर भेज दे।' वह सकते हैं इस किताब में एक इंकलाबी शायर और उनकी पत्नी के व्यक्तित्व का बिल्कुल नया पहलू हमारे सामने उभार रहा होता है। *

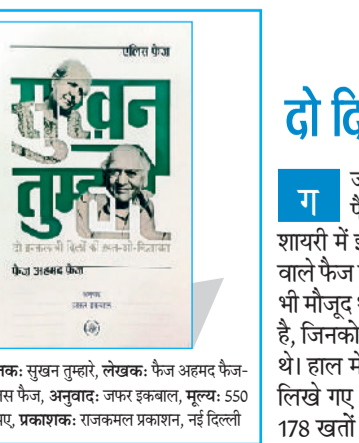
लघुकथा / डॉ. रंजना जायसवाल

खो या-पाया कैप में उस बूढ़े बाबा को बेटे छह घंटे हो गए थे। रात गहराती जा रही थी। अभी तक उन्हें कोई दूढ़ने भी नहीं आया था। बाबा की आंखें एक आशा के साथ हर आदत के साथ दरवाजे तक जातीं, लेकिन वह निराश होते। कैप के कर्मचारी की ड्यूटी बदलने का समय हो गया था। नए कर्मचारी ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए बाबा से पूछा, 'आप कहां से आए हैं?' 'बेटा काफी दूर से आए हैं।' 'कुछ नाम तो होगा।' 'नाम...' बाबा ने याद करने की कोशिश की। 'किसके साथ आए हैं?' 'कलुवा, हमारा इकलौता बेटा' 'कुंभ नहाए आए थे?' 'हमारा बेटाव्याह के दस बरस के बाद पैदा हुआ था। उसकी अम्मा मन्नत की रही, गंगा मैया को साड़ी चढ़ाएगी पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। अब जड़बे तब जड़बे करते-करते बख्त निकल गया। उसकी अम्मा ने मरते बख्त कसम ली थी। बचुवा के साथ मन्नत उतारें आए रहे। कुंभ नहाए लेब और मन्नत भी उतार देव।' 'बेटा कहा है बाबा?' 'हमसे बोला कुछ खाए का सामान लेने जाए रहे। इहां बैठे रहो हम अबही आत है।' 'फिर?' 'हमको बैठाकर पता नहीं कहां चला गया?' पुलिस वाले हमको इहां पहुंचा गए।

डुबकी



बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा।' बाबा की आंखों में अपने बेटे कलुवा के लिए चिंता उभर आई। कर्मचारी समझ चुका था, बीते कुछ दिनों में बाबा जैसे न जाने कितने लोग अपनों की तलाश और इंतजार में भटक रहे थे। 'बाबा, दस बार माइक पर कलुवा का नाम उसका जा चुका है। फोन नंबर याद है उसका?' 'फोन?' 'वापसी कब थी?' 'छ-बजे की ट्रेने थी।' 'पर बाबा अब तो नौ बज रहे हैं।' 'नौ।' बाबा की आंखों के जुगनु धूप पड़ गए। 'कलुवा आता ही होगा। हमें लिए बिना कैसे जाएगा?' बाबा ने धीरे से बुदबुदाया। सामने गंगा मैया मंद-मंथर गति से बह रही थी। वह एक और पाप की साक्षी थी। जिसे कोई डुबकी धुल नहीं सकती थी। *



पुस्तक चर्चा / विज्ञान मूषण

दो दिलों की खत-ओ-किताबत जलील-नज्मो का शायद ही कोई ऐसा कद्रदान होगा, जो फैज अहमद फैज के नाम से नावाकिफ हो। अपनी शायरी में इंकलाबी तेवर और हुकूमत की बंदियों को चुनौती देने वाले फैज के भीतर एक नाजुक दिल पति और बेहद जज्बाती पिता भी मौजूद था, इसकी बानगी उनके द्वारा लिखे उन खतों में दिखती है, जिनको उन्होंने कैद के दौरान अपनी पत्नी और बच्चों को लिखे थे। हाल में छपकर आई किताब 'सुखन तुम्हारे' में फैज के द्वारा लिखे गए 135 खत और उनकी पत्नी पुलिस के द्वारा लिखे गए 178 खतों को संकलित किया गया है। वर्ष 1951 में पाक सरकार



संजय के दीक्षित

तरकश

छत्तीसगढ़ में उपचुनाव-1

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया है, उनमें छत्तीसगढ़ की दो सीटें भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कोटे से राज्यसभा में गए केंटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम की सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। चूकि विधानसभा में बीजेपी के अब 54 विधायक हैं, इसलिए इस बार पार्टी को एक सीट मिलना निश्चित है। बची एक सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। कांग्रेस से अबकी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की दावेदारी की बड़ी चर्चा है। महंत विधानसभा से लेकर लोकसभा के लिए कई-कई बार चुने जा चुके हैं। कई मौकों पर उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट भी की है। वैसे भी महंत जी किस्मत के बड़े धनी हैं...पद उनके पास खुद से चलकर आते हैं। इसलिए, इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि पार्टी कहीं उनकी अधूरी इच्छा इस बार पूरी न कर दें। महंतजी अभी 73 के हैं, राज्यसभा में जाने के बाद लगभग 80 साल तक दिल्ली में रहने का सम्मानजनक इंतजाम हो जाएगा। वैसे हर बड़े राजनीतिज्ञों की तरह महंतजी का भी अपना एक सपना है...उनके ठीकठाक रहते सियासत में उनके सूरज का उदय हो जाए। और इसके लिए राज्यसभा चुनाव से बढ़ियां मौका क्या हो सकता है...जांजगीर, सब्ती में इस समय सारे विधायक कांग्रेस के हैं...फिर बात बेटे की, तो महंतजी की पकड़ सभी पार्टियों में है...बेटे की नैया पार करा ही लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आजादी के बाद देश की सियासत में एक नया रिकार्ड बनेगा। एक परिवार के पति राज्यसभा, पत्नी लोकसभा और बेटा विधानसभा में।

छत्तीसगढ़ में उपचुनाव-2

राज्यसभा के लिए टीएस सिंहदेव भी कांग्रेस से स्वाभाविक दावेदार होंगे। गांधी परिवार से नजदीकियों के बाद भी उनकी किस्मत बार-बार दगा दे जा रही। न वे मुख्यमंत्री बन पाए और न ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने दिया जा रहा। दूसरा, अगर पीसीसी चीफ बदलना होगा तो राज्यसभा के लिए दीपक बैज की दावेदारी प्रबल हो जाएगी। तीसरा नाम भूपेश बघेल का है। वैसे, भूपेश का चांस कम प्रतीत होता है। भूपेश जननेता हैं...कांग्रेस पंजाब से लेकर असम तक उनका उपयोग कर रही है। मगर राजनीत में कब, क्या हो जाए कौन जानता है। भूपेश अगर राज्यसभा गए तो फिर पाटन से उनके बेटे चैतन्य की विधायकी तय हो जाएगी। याने पाटन में उपचुनाव होगा।

बीजेपी और सरप्राइज

राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से चरणदास महंत की दावेदारी हो या फिर फूलोदेवी नेताम को रिपीट करने की...कम-से-कम अटकलें तो लगाने की गुंजाइश है। सत्ताधारी पार्टी की बात जुदा है। बीजेपी में आजकल इस कदर चौंकाने वाले फैसले हो रहे कि बड़े-से-बड़े लीडरों को कुछ पता नहीं होता। पिछली बार का राज्यसभा का वाक्या याद ही होगा। बीजेपी के लोगों को नहीं पता था कि देवेंद्र प्रताप सिंह हैं कौन? उनका नाम इतना अनजान था कि सोशल मीडिया में यूपी के देवेंद्रप्रताप की फोटो लगाकर लोग भाजपा का लगे टारगेट करने...कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी आयातित नेता को राज्यसभा भेज दिया। बीजेपी की लिस्ट आने के करीब आधे घंटे बाद जाकर क्लियर हो पाया कि देवेंद्र प्रताप सिंह रायगढ़ के रहने वाले हैं। इस बार भी राज्यसभा चुनाव में कुछ वैसा ही होगा। हां, इतना जरूर है कि प्रदेश की सियासत में ओबीसी और आदिवासी का कोटा फुल है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो ओबीसी से डिप्टी सीएम समेत सात मिनिस्टर। लिहाजा, अनुसूचित जाति या सामान्य वर्ग से गुंजाइश

बन सकती है।

बाहरी प्रत्याशी

छत्तीसगढ़ बनने के बाद अप्रैल 2002 में राज्यसभा की दो सीटों के लिए पहला चुनाव हुआ था। उसमें कांग्रेस से मोतीलाल वीरा और रामाधर कश्यप चुने गए थे। उसके बाद अभी तक 22 राज्यसभा सदस्यों के चुनाव हुए हैं। इसमें बीजेपी ने हमेशा लोकल को मौका दिया, कांग्रेस ने पांच बार बाहरी प्रत्याशियों को राज्यसभा में भेजा। सबसे पहले जून 2004 में मोहसिना किदवाई छत्तीसगढ़ से निर्वाचित हुईं। जून 2020 में उन्हें फिर रिपीट किया गया। उसके बाद 2018 से 2023 के बीच सबसे अधिक तीन बार ही उम्मीदवारों को कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा। केंटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन। मोतीलाल वीरा चूकि कद्दावर नेता रहे इसलिए वे 18 साल तक एक कोटा अपने पास रखा। वरना, और दो-एक बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस से राज्यसभा में पहुंच गए होते। हालांकि, लोकल बांडी की अनिच्छा के बाद भी एक सरकार में तीन-तीन बाहरी लोगों को राज्यसभा में भेजकर कांग्रेस अंजाम भुगत चुकी है, इसलिए इस बार कांग्रेस के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष चेंज?

कांग्रेस पार्टी ने चरणदास महंत के राजनीतिक कद और संसदीय अनुभवों को देखते भले ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया मगर उनका स्वभाव नेता प्रतिपक्ष वाला नहीं है। यही वजह है कि पार्टी सदन में ऐसी आक्रमकता चाहती है, वैसे कुछ हो नहीं रहा। अलबत्ता, एकाधिक बार नेता प्रतिपक्ष सरकार की भी सराहना कर चुके हैं। महंतजी राज्यसभा में जाएं या नहीं, कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष को लेकर संवेदनशील है। अगर नया नेता चुनने का अवसर आया तो जाहिर तौर पर दो नाम केंद्र में होंगे। उमेश पटेल और देवेंद्र यादव। भूपेश बघेल का नाम बड़ा जरूर है मगर पार्टी उनका उपयोग दूसरों प्रदेशों में कर रही है। देवेंद्र तेज-तरंग विधायक होने के साथ सतनामी समुदाय के मसले पर जेल जाकर अपना कद बढ़ा चुके हैं तो उमेश पटेल के साथ नंदकुमार पटेल का नाम जुड़ा है। विधानसभा में इस समय उमेश बढ़ियां परफार्म कर रहे हैं। भविष्य में अगर नेता प्रतिपक्ष चुनने का समय आया तो बहुत संभावना है कि उसके लिए ये दो नेता ही तगड़े दावेदार होंगे।

पूत के पांव पालने में

छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य कहे या एसडीएम का? शायद ही किसी स्टेट में ऐसा हुआ होगा, जब कोई सब डिवीजन मजिस्ट्रेट दो बार जेल गया हो। मगर छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, जब सात साल की सर्विस में अफसर को दो बार जेल जाना पड़ा और दो बार सरपेंड। राप्रसे अधिकारी करुण डहरिया को गरियाबंद में 20 हजार रिश्त लेते एसीबी ने ट्रेप किया था। वे तीन महीने जेल में रहकर छूटे और फिर जैसा कि देश के सिस्टम में होता है, निलंबन से बहाल होकर फिर से एसडीएम बन गए। पूत के पांव जब पालने में दिख गया था, तब तो बलरामपुर कलेक्टर रिमजिएस एक्का को उन्हें एसडीएम नहीं बनाना था। मगर पिछले दो साल से वे कुसमी सब डिवीजन के प्रमुख बने बैठे थे। और ग्रामोणों से मारपीट और मौत केस में उन्हें जेल जाना पड़ गया।

कमाऊ पूत

कलेक्टर पहले काबिल डिप्टी कलेक्टरों को एसडीएम बनाते थे। मगर अब एसडीएम बनाने के पैरामीटर बदल गए हैं। मैदानी इलाकों में 25 परसेंट तक काबिलियत चल जाता है, बस्तर, सरगुजा में हंड्रेड परसेंट कमाऊ पूत चाहिए। जो एसडीएम ज्यादा पैसा लाकर देगा, कलेक्टर के वे उतने ही करीबी और चेहेते होते हैं। कलेक्टरों को इससे

कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह डिप्टी कलेक्टर किन-किन धतकरमों में लिपट है या लिपट रहा है। कलेक्टर हों या नेता-मंत्री सभी को आखिर कमाऊ पूत ही तो चाहिए।

बड़ा सवाल

बलरामपुर के एसडीएम कांड से सवाल उठता है, क्या रिश्त लेते पकड़े गए अधिकारियों, कर्मचारियों को फिर से महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जानी चाहिए? छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं, जो रिश्त लेते जेल की हवा खाकर लौटने के बाद फिर से मलाईदार कुर्सी पर बैठे हैं। जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही सरकार को ऐसे मुलाजिमों की एक लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि उन्हें अहम पदस्थापनाओं से अलग रखा जा सके। क्योंकि, ऐसे अफसरों के साथ ऑन बिल्ट प्रॉब्लम रहता है...आगे चलकर फिर सरकार की साख को डेंट करते हैं।

बस्तर हनीमून डेस्टिनेशन

80 की दशक में जैसा बस्तर था...अफसरों के लिए वैसा ही...हनीमून डेस्टिनेशन जैसा बनता जा रहा है। माओवादियों के चलते पहले तो जान सांसत में पड़ी होती थी, न जाने किस पल क्या हो जाएगा? अधिकारी बस्तर से मीटिंग में रायपुर आने से डरते थे। बहुत आवश्यक हुआ तो देर रात प्रायवेट गाड़ी में बिना गनमैन के, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकलते थे। कोशिश रहती थी, सुबह के पहले-पहले कम-से-कम कांकेर क्रॉस कर जाएं। मगर अमित शाह ने बस्तर की रौनक फिर से लौटा दी है। सरकार भी युवा अधिकारियों पर इनायत बरत रही है। न्यू कपल को अगल-बगल के जिलों में पोस्टिंग दी जा रही। इससे हो ये रहा कि वीकेंड में कई-कई जिला मुख्यालय खाली हो जा रहे। न्यू कपल हैं तो दोनों करना चाहिए। काम भी खूब और इंजॉय भी।

चना-मूर्त जैसे आईएएस

एक तो दिग्विजय सिंह ने छोटे हुए अफसरों को छत्तीसगढ़ भेज दिया। उपर से रही-सही कसर पीएससी ने पूरी कर दी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पीएससी परीक्षा निरस्त कर दी थी मगर सरकार ने उदारता बरतने में कोई कमी नहीं की...सबके सब आईएएस बन गए। पिछले साल भी दर्जन भर अधिकारियों में से एकाध ही आईएएस बनने लायक रहे होंगे, और इस बार सात में भी कमीवेष वही हाल रहा। छत्तीसगढ़ में अब हालात ऐसे बनते जा रहे कि लोग दिग्विजय सिंह को कोसना बंद कर देंगे। इस समय मुआवजा घोटालों से लेकर अनेक कर्मकांडों में डिप्टी कलेक्टर दागदार हो रहे...जेल जा रहे, देखिएगा कुछ सालों बाद ये सबके सब भारतीय प्रशासनिक सेवा का तमगा लगाकर घूमेंगे। क्योंकि, 50 खोखा कमा लिया तो उसमें से पांच-सात खोखा फेंकने में उनके घर से क्या जाएगा? फंडा यह है कि जमकर कमाओ, जमकर खर्च करो और फिर आईएएस बन जाओ। बाकी आम पब्लिक छत्तीसगढ़ियां, सबले बढ़ियां...पर ताली बजाता रहे।

संगठन मंत्री का प्रमोशन!

छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साय के प्रमोशन की इन दिनों बड़ी चर्चा है। वैसे भी पिछले तीन महीने से छत्तीसगढ़ से लगभग वे बाहर ही हैं। बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के मोर्चे पर लगा रखा है। जाहिर है, पवन साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान काफी काम किया था। पार्टी अब उन्हें इसका इनाम देना चाहती है। पवन साय को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया जा सकता है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनने का मतलब होगा, वे एकाधिक राज्यों के प्रभारी होंगे। पवन साय के प्रमोशन से उनके समर्थक क्या सोच रहे हैं, ये तो नहीं मालूम। मगर ये जरूर पता है कि पार्टी में जल्द कुछ अहम बदलाव होंगे। जाहिर है, प्रमोशन होने पर पवन की जगह कोई नया आदमी संगठन प्रभारी

बनकर आएगा। फिर नितिन नबीन की जगह प्रदेश प्रभारी की भी नियुक्ति होगी।

ओपी के पिटारे से क्या?

जिस राज्य में बजट का 40 परसेंट हिस्सा कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन और 35 परसेंट फ्रीडोम में निकल जा रहा हो, वहां के बजट से कोई चमत्कारित उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के खजाने की यह स्थिति है कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता, जब 15 तारीख क्रॉस करते ही वित्त विभाग के अधिकारियों की पेशानी पर बल नहीं पड़ते हों। हर महीने 2500 करोड़ वेतन और करीब 800 करोड़ महतारी वंदन याने 3200 करोड़ चाहिए-ही-चाहिए। फिर भी, ओपी पढ़े-लिखे मिनिस्टर हैं, किल्लतों के बावजूद कुछ हटकर करने का प्रयास करेंगे ही। अदेशा है कि इस बार बजट में शहरी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए ठीकठाक राशि का प्रावधान किया जाएगा। खासकर, बिलासपुर और रायपुर को संवारने पर। युवाओं और रोजगार से जुड़ी कुछ अहम घोषणाओं की भी उम्मीदें हैं।

नेताओं की आंखों में धूल

छत्तीसगढ़ के ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। एजुकेशन में नित नए प्रयोग और नवाचार किए जा रहे हैं। मगर यह भी सन्देह रहे कि रिजल्ट को लेकर अफसरशाही नेताओं की आंखों में धूल झांकने का भी काम करती है। खासकर, स्कूल शिक्षा में। नकल के नाम पर यूपी-बिहार बदनाम थे। वहां अब स्थिति बदल गई है। और छत्तीसगढ़ में? स्कूल शिक्षा में छत्तीसगढ़ पिछले 25 सालों से देश में नीचे से तीसरे स्थान से उपर नहीं आ पाया। बता दें, कुछ बरसों पहले दो कलेक्टरों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी कि अपने जिले का नंबर बढ़ाने स्कूल वालों को कुछ भी करने के लिए कह डाला था। जाहिर है, छत्तीसगढ़ के कलेक्टरों में अभी भी श्रेय लेने की होड़ है कि उनके जिले से इतने लोग मॉरिट में आए। चिंतन पर इस पर भी होनी चाहिए कि रिमोट एरिया के स्कूलों में रिजल्ट इतने बढ़ियां कैसे आ जाते हैं। और, अगर ऐसा ही रहा तो सवाल उठता है...छत्तीसगढ़ के ह्यूमन रिसोर्स का क्या होगा? इस पर मनन करना चाहिए।

बजट सत्र में ट्रांसफर

ब्यूरोक्रेसी में ऐसा परसेप्शन चला आ रहा, बजट सत्र में ट्रांसफर नहीं होते। मगर छत्तीसगढ़ में ऐसा कई बार हो चुका है। इसी सरकार ने मानसून सत्र के दौरान ट्रांसफर किया था। बहरहाल, 23 फरवरी से बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। और 24-25 फरवरी के आसपास बलौदा बाजार कलेक्टर दीपक सोनी सेंट्रल डेप्युटेशन के लिए रिलीव होंगे। 24-25 इसलिए क्योंकि 24 को गिरौदापुरी मेला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सरकार उन्हें कार्यमुक्त कर देगी। सवाल उठता है, बलौदा बाजार का अगला कलेक्टर कौन होगा? कलेक्ट्रेट को जलाने जैसी घटना के बाद तो सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। लिहाजा, बतौर कलेक्टर दो-एक जिला करने वाले अनुभवी आईएएस अफसर को ही बलौदा बाजार भेजा जाएगा। हो सकता है, इस चक्कर में एक छोटा चेन बन जाए।

अंत में दो सवाल आपसे

1. क्या छत्तीसगढ़ के इस बजट में रायपुर-भिलाई में मेट्रो रेल की घोषणा हो सकती है?
2. एक मंत्री का नाम बताएं, जो कुर्सी की स्थिरता के लिए कामख्या के एक पंडित से यज्ञ करवाएं हैं?



Business Ka Naya Address

अब और भी प्रीमियम

SHRI DWARIKA BUSINESS CENTER PHASE II



पहले फेज़ के शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब अगला मौका आपके लिए

रायपुर के विकसित होते कमर्शियल ज़ोन में स्मार्ट निवेश का स्मार्ट विकल्प

- ✓ आसान किस्तों में भुगतान
- ✓ 80% तक फायनेंस उपलब्ध
- ✓ सुरक्षित और लाभदायक निवेश

डुमरतराई का प्राइम लोकेशन,

आज का निर्णय, कल की सफलता



Project Developed By -
SHRI DWARKA BUILDERS

श्री द्वारिका बिल्डर्स
औषधि वाटिका, मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास,
डुमरतराई, रायपुर (छत्तीसगढ़)



76173 90000,
88179 55000, 70677 53237



SCAN FOR LOCATION

सुरक्षित निवेश के कई मजबूत विकल्प, मिलेगा बढ़िया रिटर्न

- पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस और सुकन्या जैसी योजनाएं दे रही हैं आकर्षक ब्याज और टैक्स लाभ
- कम जोखिम में स्थिर आय और लंबी अवधि में मजबूत फंड बनाने के विकल्प
- बैंक एफडी से आगे बढ़कर सोचें, सरकारी योजनाओं में छिपा है बेहतर रिटर्न



बिजनेस डेस्क

आज के दौर में निवेशकों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है पूंजी की सुरक्षा और स्थिर रिटर्न। शेयर बाजार की अस्थिरता से घबराने वाले या जोखिम कम लेना चाहने वाले लोग आमतौर पर बैंक एफडी का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या एफडी ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है? असल में, सरकार समर्थित कई ऐसी योजनाएं हैं जो न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि कई मामलों में एफडी से बेहतर ब्याज भी देती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही भरोसेमंद निवेश विकल्पों के बारे में, जहां सुरक्षा के साथ अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है।

कंपाउंडिंग के लिए सबसे बेहतर

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) अगर आपको लक्ष्य लंबी अवधि में सुरक्षित तरीके से बड़ा फंड बनाना है, तो पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्प है।
 - निवेश अवधि: 15 वर्ष
 - वर्तमान ब्याज दर: 7.1% (सरकार द्वारा तिमाही आधार पर तय)
 - अधिकतम निवेश: 15 लाख रुपये प्रति वर्ष
 - टैक्स लाभ: धारा 80सी के तहत छूट
 - पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत है इसका इंडेक्ड स्टैटस निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों टैक्स-फ्री होती हैं। यह योजना खासकर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो रिटायरमेंट या बच्चों की उच्च शिक्षा जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं।
2. **नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी)**
 - यदि आप 5 साल की अवधि के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो एनएससी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
 - निवेश अवधि: 5 वर्ष
 - ब्याज दर: लगभग 7.1%
 - टैक्स लाभ: 80सी के तहत छूट
 - एनएससी में निवेश की गई राशि सुरक्षित रहती है और तय ब्याज दर के अनुसार परिपक्वता पर रिटर्न मिलता है। यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर है जो मध्यम अवधि के लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं और जोखिम नहीं लेना चाहते।
3. **सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस)**
 - यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।
 - निवेश अवधि: 5 वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है)
 - ब्याज दर: लगभग 8% से अधिक (तिमाही समीक्षा के अधीन)
4. **पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस)**
 - अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ हर महीने नियमित आय चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक बेहतर विकल्प है।
 - निवेश अवधि: 5 वर्ष
 - ब्याज दर: लगभग 7.4%
 - मासिक ब्याज भुगतान
5. **सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)**
 - बेटीयों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह योजना विशेष रूप से बनावी गई है।
 - पात्रता: 10 वर्ष या उससे कम आयु की बेटी
 - निवेश अवधि: 15 वर्ष
 - मैच्योरिटी: 21 वर्ष
 - अधिकतम निवेश: 15 लाख रुपये प्रति वर्ष
 - ब्याज दर: लगभग 8.2%
 - एसएसवाई वर्तमान में सबसे अधिक ब्याज देती है।

ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में यह सबसे लुभावना मौका

जानकारी
बिजनेस डेस्क

ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में एक लाइन सबसे ज्यादा लुभाती है वो है 'नो कॉस्ट' ईएमआई। छोटी-छोटी किस्तें देखकर खरीदारी का फैसला आसान लगने लगता है। दिमाग कहता है "इतनी सी ईएमआई है, अभी ले लेते हैं।" लेकिन निवेश और व्यक्तिगत वित्त के नजरिए से देखें तो 'नो कॉस्ट' ईएमआई उतनी सरल नहीं, जितनी दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इसमें कोई लागत नहीं होती? या फिर लागत सिर्फ नजर नहीं आती?

'नो कॉस्ट' ईएमआई होती क्या है?

सरल शब्दों में, 'नो कॉस्ट' ईएमआई का मतलब है कि आप किसी प्रोडक्ट की कीमत किस्तों में चुकाते हैं और आपको अलग से ब्याज नहीं देना पड़ता। यानी कुल ईएमआई जोड़ने पर रकम उतनी ही होगी जितनी प्रोडक्ट की कीमत। लेकिन बैंक या फाइनेंस कंपनी बिना कमाई के पैसा उधार नहीं देती। तो फिर ब्याज कौन दे रहा है? यहीं से असली खेल शुरू होता है।

बैंक की कमाई कैसे होती है?

जब आप ईएमआई चुनते हैं, तो आमतौर पर प्रोडक्ट पर मिलने वाला सीधा डिस्काउंट कम कर दिया जाता है। उसी घंटे हुए डिस्काउंट से बैंक का ब्याज एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब ये कि कागजों में आपको "ब्याज नहीं" दिखाता है। लेकिन आपको मिलने वाला फायदा पहले ही कम कर दिया जाता है। बैंक को उसका हिस्सा चला देता है, और ग्राहक को लगता है कि वह बिना अतिरिक्त खर्च के सुविधा ले रहा है।

एसआईपी संपत्ति निर्माण का एक आसान और व्यवस्थित तरीका बिना योजनाबद्ध निकासी निवेश को कर देता है बर्बाद

बिजनेस डेस्क

जनवरी 2026 में निवेशकों ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए म्यूचुअल फंड में 31,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। एसआईपी अब आदत जैसी बन गई है। यह संपत्ति निर्माण का एक आसान और व्यवस्थित तरीका बन गया है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आप इसका उपयोग करना शुरू करते हैं। बिना योजनाबद्ध निकासी रणनीति के वर्षों का अनुशासित निवेश जल्दी ही बिखर सकता है। इसलिए हर एसआईपी के साथ एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) होना भी जरूरी है। एसआईपी संपत्ति संचय का एक प्रभावी साधन है, लेकिन यह सुचारु परिणाम की गारंटी नहीं देता। इसलिए एसआईपी से बाहर निकलने का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका एसआईपी कितने समय तक चला या आपने इसे किस बाजार परिस्थिति में शुरू किया। अंतिम चरण में बाजार में गिरावट आपको योजनाओं को पटरी से उतार सकती है। मान लीजिए एक निवेशक ने जनवरी 2005 में एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी शुरू की। लक्ष्य था 2020 के मध्य तक घर की 26 लाख रुपये की कमी। पोर्टफोलियो को दोबारा संभलाने में लगभग आठ महीने लग गए। यदि निवेशक ने लक्ष्य तिथि से 12-18 महीने पहले एसडब्ल्यूपी के माध्यम से चरणबद्ध निकासी शुरू कर दी होती तो कुछ मुनाफा सुरक्षित किया जा सकता था। एसडब्ल्यूपी मूलतः एसआईपी का उल्टा है। नियमित अंतराल पर निश्चित रकम निवेश करने के बजाय आप तय समयावधि में नियमित रूप से निश्चित राशि निकालते हैं। जैसे-जैसे लक्ष्य नजदीक आता है, एसडब्ल्यूपी एक संतुलित और क्रमिक निकासी का मार्ग तैयार करता है।



एसडब्ल्यूपी है वितरण की संरचना

इस संरचना के दो प्रमुख लाभ हैं। पहला यह अंतिम समय की बाजार अस्थिरता से अर्जित लाभ के एक हिस्से को सुरक्षा करता है। दूसरा जो राशि नहीं निकाली जाती, वह निवेशित बनी रहती है और अंतिम चरण में बाजार में गिरावट आपको योजनाओं को पटरी से उतार सकती है। मान लीजिए एक निवेशक ने जनवरी 2005 में एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी शुरू की। लक्ष्य था 2020 के मध्य तक घर की 26 लाख रुपये की कमी। पोर्टफोलियो को दोबारा संभलाने में लगभग आठ महीने लग गए। यदि निवेशक ने लक्ष्य तिथि से 12-18 महीने पहले एसडब्ल्यूपी के माध्यम से चरणबद्ध निकासी शुरू कर दी होती तो कुछ मुनाफा सुरक्षित किया जा सकता था। एसडब्ल्यूपी मूलतः एसआईपी का उल्टा है। नियमित अंतराल पर निश्चित रकम निवेश करने के बजाय आप तय समयावधि में नियमित रूप से निश्चित राशि निकालते हैं। जैसे-जैसे लक्ष्य नजदीक आता है, एसडब्ल्यूपी एक संतुलित और क्रमिक निकासी का मार्ग तैयार करता है।

सेवानिवृत्ति से आगे की भी सोचें

परंपरागत रूप से एसडब्ल्यूपी को रिटायरमेंट आय के साधन के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन यह धारणा बदल रही है। एसडब्ल्यूपी जीवन के विभिन्न चरणों में एक लचीला और कम-कुशल नकदी प्रवाह समाधान बनकर उभर रहा है। यह लोन की ईएमआई, बच्चों की फीस या अनियमित आय से जुड़े जीवनशैली खर्च जैसे नियमित खर्चों में मदद कर सकता है। एसडब्ल्यूपी प्रोविडेंट, कंसल्टेंट या चक्रिय आय वाले व्यवसायियों के लिए भी उपयोगी है। अधिक आय वाले महीनों में अतिरिक्त कमाई निवेश की जा सकती है, जबकि एक छोटा एसडब्ल्यूपी निश्चित मासिक खर्चों के लिए स्थिर आय प्रदान कर सकता है। यहां तक कि एकमुश्त लक्ष्यों जैसे शादी या घर की मरम्मत के लिए भी एसडब्ल्यूपी चरणबद्ध निकासी की सुविधा देता है, जिससे टाइमिंग जोखिम कम होता है और शेष पूंजी निवेशित बनी रहती है।

सिर्फ एसआईपी नहीं एसडब्ल्यूपी भी जरूरी

बकेट रणनीति भी बनाएं

रिटायरमेंट में हर फंड एसडब्ल्यूपी के लिए उपयुक्त नहीं होता। विशेषज्ञ तीन-बकेट रणनीति सुझाते हैं। तीन साल के खर्च लिक्विड फंड में, चौथे से सातवें वर्ष के खर्च केजरवेटिव हाइब्रिड फंड में और दीर्घकालिक निवेश इक्विटी में ताकि मुद्रास्फीति को मात दी जा सके। निकासी पहले बकेट से शुरू होती है। जैसे-जैसे वह कम होता है, दूसरे बकेट से उसे भरा जाता है और बाद में तीसरे बकेट से। यह स्तरीय संरचना निरंतर अर्थात् खर्चों को इक्विटी की अस्थिरता से बचाती है और दीर्घकालिक वृद्धि को बनाए रखती है।

चक्र को पूरा करना जरूरी

हर वित्तीय यात्रा व्यक्तिगत लक्ष्यों, आय पैटर्न और जोखिम सहनशीलता से प्रभावित होती है। लेकिन सिद्धांत सामूहिक है। वितरण योजना के बिना संवय संक्रमण आवश्यक है। सही तरीके से किया जाए तो यह साइडवरी चक्रवृद्धि की शक्ति को जारी रखते हुए आपको नियमित आय भी देती रहती है।

संक्रमण की योजना भी हो

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश के तुरंत बाद एसडब्ल्यूपी शुरू नहीं करना चाहिए। निकासी शुरू होने से पहले पोर्टफोलियो को बढ़ाने का समय चाहिए। बहुत जल्दी शुरूआत करने से यदि बाजार अस्थिर हो जाए, तो मूलधन पर असर पड़ सकता है। कर देखा भी इसका एक बड़ा लाभ है। प्रत्येक एसडब्ल्यूपी किस्त में मूलधन और पूंजीगत लाभ दोनों शामिल होते हैं, लेकिन कर केवल लाभ वाले हिस्से पर लगता है। कम से कम एक वर्ष तक निकासी टालने से इक्विटी निवेश दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के दायरे में आ जाता है, जिसमें सालाना 1.25 लाख रुपये तक के लाभ पर छूट मिलती है। अनिवार्य लक्ष्यों के लिए आदर्श रूप से लक्ष्य तिथि से 2-3 वर्ष पहले एसडब्ल्यूपी शुरू कर देना चाहिए। मले ही कॉर्पोरेट थोड़ा कम हो। अंतिम वर्ष तक इंतजार करने से जोखिम बढ़ जाता है। चरणबद्ध निकासी परिणामों को संतुलित बनाती है।

कितनी निकासी सुरक्षित है?

दीर्घकालिक स्थितियों जैसे सेवानिवृत्ति में निकासी दर यह तय करती है कि बचत 20-30 वर्षों तक चलेगी या समय से पहले खत्म हो जाएगी। जोखिम केवल बाजार की अस्थिरता नहीं, बल्कि सीवेंस-ऑफ-रिटर्न्स का भी होता है। यदि शुरूआती वर्षों में खराब रिटर्न के दौरान निकासी होती है तो कॉर्पोरेट से घट सकता है। एसआईपी के विपरीत, जहां गिरते बाजार में अधिक युनिट जमा होती हैं, एसडब्ल्यूपी में गिरावट के दौरान समाप्त नकदी प्रवाह के लिए अधिक युनिट बेचनी पड़ती हैं। इसलिए निकासी दर संतुलित और संवधानीपूर्ण होनी चाहिए। आदर्श रूप से निकासी दर पोर्टफोलियो के दीर्घकालिक समावित रिटर्न से कम होनी चाहिए। एक सामान्य नियम यह है कि निकासी वास्तविक रिटर्न यानी मुद्रास्फीति समायोजित रिटर्न के आधार पर तय हो। यदि अपेक्षित रिटर्न 10% और मुद्रास्फीति 5% है, तो निकासी 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्थिरता बनाए रखने के लिए निकासी दर अपेक्षित रिटर्न से 2-3 प्रतिशत अंक कम रखनी चाहिए। वैश्विक शेयर अक्सर 3.5-4% को एक टिकाऊ दर मानता है, लेकिन इसकी उपयुक्तता एसेट आवंटन, जीवन प्रत्याशा और जीवनशैली को जख्म करेगा। प्रदर्शन के आधार पर समायोजित होने वाली डायनमिक निकासी रणनीतियां भी मजबूती बढ़ा सकती हैं।

फंड तैयार करने की जल्दबाजी छोड़िए, एसआईपी को समय दें

बिजनेस डेस्क। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) आज म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है। छोटे-छोटे मासिक निवेश के जरिए बड़ा फंड तैयार करने का यह अनुशासित माध्यम है। लेकिन एक सवाल लगभग हर निवेशक के मन में आता है। एसआईपी में रिटर्न असली रफ्तार कब पकड़ता है? कई निवेशक 1-2 साल में शानदार मुनाफे की उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो वे एसआईपी बंद भी कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एसआईपी का असली फायदा समय के साथ खुलकर सामने आता है।

शॉर्ट टर्म में क्यों निराश कर सकता है एसआईपी?

अगर आप 1 से 3 साल की अवधि में एसआईपी का प्रदर्शन देखें, तो तर्कहीन उतनी आकर्षक नहीं दिखती। ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर निफ्टी 50 पर आधारित एसआईपी के रिटर्न का विश्लेषण बताता है कि छोटे समय में रिटर्न कई बार पलैट या निगेटिव भी रहा है।

कुछ अवधियों में

1. साल का एक्सआईआरआर रिटर्न -60% से ज्यादा तक गिरा
2. साल में -40% के आसपास
3. साल में -20% से ज्यादा गिरावट

शुरुआती रिटर्न कमजोर

यह सुनकर घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका कारण समझना जरूरी है। शेयर बाजार साइकिल में चलता है। कभी तेजी, कभी गिरावट। यदि आपने एसआईपी की शुरुआत बाजार के ऊपरी स्तर पर की और उसके बाद गिरावट आई, तो शुरुआती रिटर्न कमजोर दिख सकते हैं। इसे ही टाइमिंग रिस्क कहते हैं। शॉर्ट टर्म में बाजार की दिशा आपके निवेश अनुभव को प्रभावित करती है।

5 साल के बाद बदलती है तस्वीर

जैसे-जैसे निवेश की अवधि 5 साल के आसपास पहुंचती है, उतार-चढ़ाव का असर कम होने लगता है।

15 साल के अधिकांश रोलिंग पीरियड में एसआईपी का रिटर्न 5% से 10% के बीच रहा है। लंबी अवधि में रिटर्न का मौका मिलता है।

दो चीजें काम करती हैं

- 1. रुपया लागत औसत: बाजार गिरने पर आपको तय राशि से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं।
- 2. कंपाउंडिंग: शुरुआती निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आगे रिटर्न कमाता है।
- 3. शुरुआती सालों की कमजोरी संतुलित होने लगती है और निवेश स्थिरता दिखाने लगता है।

7 साल के बाद बढ़ती है रफ्तार

इतिहास बताता है कि 7 साल या उससे अधिक की अवधि में एसआईपी पर निगेटिव रिटर्न की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। डबल डिजिट रिटर्न सामान्य हो जाते हैं। यहां सबसे बड़ा बदलाव बाजार में नहीं, बल्कि निवेशक के अनुभव में आता है। बाजार गिरता है, तो आपके पास रिटर्न का पर्याप्त समय होता है। तेजी आने पर आप उस पूरी रैली का हिस्सा बनते हैं। कंपाउंडिंग का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगता है।

ऐसे समझें

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी करता है और औसतन 12% रिटर्न मिलता है, तो 3 साल में कुल निवेश 3.6 लाख पर फंड लगभग 4-4.5 लाख के

आसपास हो सकता है। 10 साल में कुल निवेश 12 लाख पर फंड 23-24 लाख से ज्यादा हो सकता है। यहीं है कंपाउंडिंग की असली ताकत।

कब शुरू करें और कितना समय दें

- 1. जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना बेहतर।
- 2. कम से कम 7-10 साल का नजरिया रखें।
- 3. बाजार गिरने पर बंद न करें, जारी रखें।
- 4. लक्ष्य आधारित निवेश करें।

असली रफ्तार कहां से

- 1. पहले 2-3 साल: उतार-चढ़ाव
- 2. 5 साल: स्थिरता
- 3. 7 साल+: कंपाउंडिंग का प्रभाव
- 4. 10 साल+: वास्तविक वेल्थ क्रिएशन

धैर्य ही असली रणनीति

एसआईपी कोई जादूई फार्मूला नहीं, बल्कि अनुशासित निवेश की प्रक्रिया है। छोटे समय में परिणाम आकर्षक न दिखें, लेकिन लंबी अवधि में यह प्रभावशाली बन जाता है। अगर आप बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन करने का धैर्य रखते हैं और निवेश को 7-10 साल का समय देते हैं, तो एसआईपी मजबूत संपत्ति निर्माण करेगी।

सस्ती किस्तों का जाल : क्या सच में 'नो कॉस्ट' है ईएमआई ईएमआई में नहीं दिखता ब्याज, लेकिन कीमत बदल जाती है



एक उदाहरण से समझिए

- 1. मान लीजिए आप 60,000 रुपये का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं।
- 2. फुल पेमेंट पर ऑफर: 5,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट
- 3. अंतिम कीमत: 55,000 रुपये
- 4. अब आप नो कॉस्ट ईएमआई चुनते हैं डिस्काउंट घटकर 2,500 रुपये रह जाता है
- 5. नई कीमत: 57,500 रुपये
- 6. आपने शुरुआत में ही 2,500 रुपये ज्यादा दे दिए।
- 7. अगर इसमें 499 प्रोसेसिंग फीस और उस पर 18% जीएसटी जोड़ दें, तो कुल खर्च लगभग 58,000 रुपये से ऊपर पहुंच सकता है।
- 8. दिखने में ईएमआई आसान थी, लेकिन कुल भुगतान बढ़ चुका है।

सबसे बड़ा भ्रम है: ईएमआई

- 1. सुविधा-सस्ता सीधा
- 2. असल में ईएमआई सिर्फ भुगतान को छोटे हिस्सों में बांटती है। खर्च कम नहीं करती।
- 3. छोटी ईएमआई दिमाग पर दबाव कम डालती है। एकमुश्त 55,000 देने से ज्यादा आसान लगता है 4,800 रुपये की मासिक किस्त देना। लेकिन कुल रकम का हिस्सा अवसर नजर अंधाज हो जाता है।
- 4. यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है—छोटे नंबर कम डरते हैं।
- 5. छिपे हुए चार्ज जिन पर कम ध्यान जाता है

ये अतिरिक्त खर्च संभव

- 1. प्रोसेसिंग फीस: 199 से 999 रुपये या उससे अधिक
- 2. जीएसटी: प्रोसेसिंग फीस या ब्याज वाले हिस्से पर 18%
- 3. ईएमआई कचरार्ज चार्ज

कब नो कॉस्ट ईएमआई सही विकल्प

- 1. हर बार नो कॉस्ट ईएमआई गारंटी नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में यह उपयोगी हो सकती है। आपके पास पूरी रकम उपलब्ध नहीं है। ईएमआई लेने से डिस्काउंट कम नहीं हो रहा। प्रोसेसिंग फीस शून्य है। आप कैश प्लेन में नेजनेट के लिए भुगतान फैलाना चाहते हैं। अगर इन शर्तों में से अधिकांश पूरी होती हैं, तो ईएमआई एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

निवेश के नजरिए से

व्यक्तिगत वित्त का एक मूल सिद्धांत है खर्च से पहले गणित करें। यदि आपके पास पर्याप्त बचत और आप फुल पेमेंट कर सकते हैं, तो अवसर वह सस्ता विकल्प होता है। ईएमआई चुनने से पहले यह सोचें।

सोचें क्या यह जरूरत है

- 1. क्या ईएमआई के कारण मैं अतिरिक्त खर्च कर रहा हूँ?
- 2. क्या मैं कई ईएमआई का बोझ एक साथ उठा रहा हूँ?
- 3. कई बार लोग एक साथ 3-4 ईएमआई ले लेते हैं। छोटी-छोटी किस्तें मिलकर बड़ी मासिक देनदारी बन जाती हैं।

मार्केटिंग बनाम समझदारी

आज का ई-कॉमर्स माहौल भावनात्मक फैसले लेने को प्रेरित करता है। अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें। लेकिन समझदार खरीदार पहले कैलकुलेशन करता है, फिर निर्णय लेता है। नो कॉस्ट ईएमआई धोखा नहीं है, लेकिन अंधेरी जानकारी मुकदसान में बदल सकती है। नो कॉस्ट ईएमआई सुविधा देती है, लेकिन हर सुविधा की एक कीमत होती है। वह वह सीधी दिखे या छिपी हुई हो। इसलिए पहले पूरा गणित समझें, कुल भुगतान जोड़ें, और फिर फैसला लें। क्योंकि समझदारी से किया गया खर्च ही असली बचत है।



कठिन समस्याओं के लिए भरोसेमंद टॉनिक

पूरे माह रहें एक्टिव, फिट एवं स्वस्थ

Clinically Tested

24x7 Helpline: 77106 44444 • www.sachisaheli.in

67 दुर्लभ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बना 'सच्ची सहेली' आयुर्वेदिक टॉनिक एवं टेबलेट्स

पहले महीने असर देखें

- कठिन दर्द
- चिड़चिड़ापन
- थकान
- कमजोरी
- कमर कटना
- इम्यूनटी

उम्र में सबसे छोटा, लेकिन कद में काफी बड़ा, 29 साल का अरबपति युवक

नई दिल्ली। एआई इंपैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन बड़ी हलचल रही। दुनिया के बड़े टेक लीडर्स जुट चुके हैं। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक सीईओ डारियो एमोडेइ की चर्चा चारों तरफ है। लेकिन एलेक्जेंडर वेंग इस समिट में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कम बात हो रही है। दिलचस्प ये है कि वेंग उम्र में सबसे छोटे हैं, लेकिन कद में काफी बड़े हैं। एलेक्जेंडर वेंग उम्र में सबसे छोटे लीडर्स में से हैं जो इस समिट में पहुंचे। मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा। एलेक्जेंडर वेंग आज मेटा की एआई स्ट्रैटेजी को लॉन्च कर रहे हैं और वो 29 साल के हैं। गौरतलब है कि एलेक्जेंडर वेंग टॉप एआई कंपनी स्केल एआई के फाउंडर रह चुके हैं।

एलेक्जेंडर वेंग युवा अरबपति
एलेक्जेंडर वेंग सिर्फ एक सामान्य टेक लीडर नहीं हैं, वह एआई इंडस्ट्री के सबसे युवा और हाई-प्रोफाइल प्रोफेशनल्स में से एक हैं। एमआईटी छोड़कर उन्होंने 2016 में स्केल एआई नाम की कंपनी शुरू की, जो एआई डेटा-लेबलिंग और मॉडल ट्रेनिंग के लिए जानकारी तैयार करती है। दुनिया की बड़ी एआई कंपनियां जैसे एनविडिया, अमेजन और मेटा जैसी कंपनियां स्केल एआई के क्लाइंट रहे हैं। इसी काम की वजह से उनकी कंपनी जल्दी ही युनिकाम बनी और फोर्ब्स के मुताबिक उनका नेट वर्थ लगभग \$3.2-\$3.6 बिलियन (करीब 28,000-31,000 करोड़) तक पहुंच गया। यानी वेंग दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल हैं।

एआई इंपैक्ट समिट में पीएम मोदी के साथ दिखे वेंग

बीच में छोड़ दी थी पढ़ाई
एलेक्जेंडर वेंग की कहानी भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ी। एआई डेटा पर काम शुरू किया। कुछ ही सालों में उनकी कंपनी अरबों डॉलर की वैल्यू तक पहुंच गई। आज वह दुनिया के सबसे युवा टेक अरबपतियों में गिने जाते हैं। एआई इंपैक्ट समिट में उनकी मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि आने वाले समय में एआई की दिशा सिर्फ उमदाज़ा सीईओ तय नहीं करेंगे। नए और युवा लीडर्स इस रेस में आगे निकल रहे हैं।

मेटा ने वेंग को ऐसे किया हायर
मेटा ने एलेक्जेंडर वेंग को हायर करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। 2025 में मेटा ने स्केल एआई में लगभग \$14.3 बिलियन (करीब 1,17,000 करोड़) का निवेश किया और कंपनी का लगभग 49% हिस्सा लिया। इसी दौरान वेंग को मेटा में सुपर इंटीलिजेंस लैब (एमएसएल) का मुख बनवाया गया। इस डील को एआई इतिहास के सबसे बड़े टेलेंट एक्चू हायर में से एक माना गया और मार्क जकरबर्ग ने खुद इसे मेटा की एआई स्ट्रैटेजी को मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम बताया।

वेंग का विजन
एआई इंपैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी से उनकी मुलाकात को सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं माना जा रहा। मेटा के लिए भारत अब सिर्फ बड़ा मार्केट नहीं है। भारत एआई का अगला बड़ा केंद्र बन रहा है। एलेक्जेंडर वेंग ने मंच से कहा कि भारत में एआई को अपनाने की रफ्तार बहुत तेज है। यहां के लोग नई टेक्नोलॉजी जल्दी अपनाने हैं। वेंग टेक्नोलॉजी, खास तौर पर एआई और सुपर इंटीलिजेंस को लेकर काफी इन्थुजियेट है। उन्होंने खुद ही कई मॉडल्स पर काम किया है। वाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई फीचर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है।

धरती के नीचे चमत्कार, 4000 करोड़ में बना इतना खूबसूरत वॉटर फॉल होटल, देखते ही रह जाएंगे दंग

बीजिंग। दुनिया में ऐसी कई इमारतें हैं, जो अपनी अनोखी आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती हैं। इस लिस्ट में चीन के एक खास होटल का नाम भी शामिल है। यह होटल एक खदान के अंदर बना है और वॉटर फॉल होटल के नाम से जाना जाता है। आइए जानें क्यों इसे यह नाम मिला और इस होटल की खासियत क्या है। खाने-पीने के लिए होटल में पानी के नीचे बना सीफूड रेस्टोरेंट, कैंटीन फाइंड डाइनिंग और क्वारी बार जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा, होटल में वॉटर स्पोर्ट्स एरिया, इफिनिटी पूल और स्पा की सुविधा भी है। रोमांच पसंद करने वालों के लिए पास के थीम पार्क में जिपलाइन, बंजी जंप, रॉक क्लाइम्बिंग और ग्लास वॉकवे जैसी गतिविधियां मौजूद हैं।

खदान के अंदर बना है होटल
चीन के शंघाई शहर के सोनजियान जिले में स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वेंडरलैंड होटल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। यह अनोखा होटल एक पुरानी खदान के अंदर बना है, जिसकी वजह से इसे क्वारी होटल या खदान होटल के नाम से भी जाना जाता है।
क्यों कहा जाता है वॉटरफॉल होटल?
होटल की सबसे खास बात इसकी संरचना है, जो 88 मीटर गहरी खदान की दीवारों में बनाई गई है। इसमें कुल 18 मंजिलें हैं, जिनमें से 16 मंजिलें और दो मंजिलें पानी के नीचे स्थित हैं। इसके सामने 90 मीटर ऊंचा कुत्रिम झरना होटल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, जिसके कारण इसे वॉटरफॉल होटल भी कहा जाता है।



4 हजार करोड़ में बनाया गया होटल
इस होटल का इतिहास काफी दिलचस्प है। इस खदान को 1950 के दशक में जापानियों ने खुद के दौरान बंद करवाने के लिए खोदा था। बाद में इसे आशिक रूप से पानी से भरकर एक आर्टिफिशियल झील में बदल दिया गया। साल 2006 में शंघाई के एक प्रांटी गुप ने इस जगह में संभावना देखी और इसे एक लक्जरी होटल में तब्दील करने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में हुई और इसे पूरा करने में करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत आई।

आराम और रोमांच का अनुभव
इस होटल में ठहरना केवल आराम का नहीं, बल्कि रोमांच का भी अनुभव है। यहां तिलफ के किनारे बने विला और पानी के नीचे बने सुइट्स हैं, जहां कांच की दीवारों से मेहमान सीधे झील के भीतर का नजारा देख सकते हैं। होटल में कुल 337 कमरे हैं, जिनमें से हर एक में वाइस-कंट्रोल सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

इनवर्टेड ग्राउंडस्केपर के नाम से भी जाना जाता है
इस होटल को डिजाइन करने के लिए कई मशहूर आर्किटेक्चर फर्म की युवा गयी। होटल की डिजाइन में फेंगशूई के प्रिंसिपल्स को अपनाया गया है और इसे इनवर्टेड ग्राउंडस्केपर कहा जाता है, क्योंकि यह ऊपर की बजाय नीचे की ओर बना है। ऊपर से देखने पर इसका आकार 'एस' जैसा दिखता है। होटल को पर्यावरण के लिए जागरूक बनाते हुए एक सिंगल यूज प्लास्टिक-फ्री होटल के रूप में विकसित किया गया है। यह एक 'बाउण्ड्रीलेस रिवाइवल प्रोजेक्ट' है, जिसमें छोड़ी हुई जमीन का इस्तेमाल किया गया है।

71 साल की बुजुर्ग महिला हैं फिटनेस की मिसाल

बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में लिया भाग

बुढ़ापे में लोग बिस्तर को दोस्त मान लेते हैं और कमजोरी के कारण काम-काज नहीं कर पाते हैं। हालांकि, कुछ बुजुर्गों का जन्वा उन्हें ऐतिहासिक चीजें करने के लिए प्रेरित करता है और वह साहस की मिसाल पेश करते हैं। ऐसा ही कुछ चीन में हुआ है, जहां 71 साल की बुजुर्ग महिला को फिटनेस ने लोगों को अचंबित कर दिया है। वह इतनी उम्र में ही फिटनेस के बावजूद भी इतनी मेहनती हैं कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लिया।
हफ्ते में 5 दिन करती हैं एक्सरसाइज : मिंगुई ने अपनी फिटनेस के बारे में बात करते हुए कहा कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी मांसपेशियां ढलने के बजाय मजबूत होती गईं। उनका कहना है, इससे साबित होता है कि उम्र चाहे जो भी हो, आप शक्ति प्रशिक्षण या अन्य एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्थिर रहने की तुलना में गतिशील रहना हमेशा बेहतर होता है। वह हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करती हैं और उनके सभी सत्र एक घंटे से लंबे होते हैं।

प्रतियोगिता में हासिल किया तीसरा स्थान
महिला का नाम सुन मिंगुई है, जो मूल रूप से मध्य चीन के एक छोटे प्रांत के मानवशास्त्र की रहने वाली हैं। उन्होंने न केवल फिटनेस प्रतियोगिता में भाग लिया, बल्कि तीसरा स्थान हासिल करके इतिहास भी रच डाला। उन्होंने इस साल जुलून में हुई राष्ट्रीय फिटनेस नवागतु कुगुवता प्रतियोगिता में मिश्रित लिंग वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसका मतलब है कि उन्होंने न केवल अपने से आधी उम्र की महिलाओं को हराया, बल्कि पुरुषों को भी मात दी।

67 की उम्र में शुरू किया था व्यावसायिक प्रशिक्षण
मिगुई रिटायर होने से पहले एक स्टल फैक्ट्री के कैफेटेरिया में काम करती थीं। व्यस्त रहते हुए भी वह रोजाना एक्सरसाइज करने का समय निकाल लेती थीं। हालांकि, रिटायर होने के बाद उन्होंने सेहतमंद बने रहने के लिए रस्सी कूकना, साइकिल चलाना और हाईकिंग करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 67 साल की उम्र में फिटनेस प्रशिक्षण शुरू किया और कुछ ही समय में सिकस-पैक और मजबूत बॉडी बना ली।

बढ़ जाएंगी एमबीबीएस की ढाई सौ सरकारी सीटें पर मेडिकल कालेजों में पढ़ाने वालों की व्यवस्था बड़ी चुनौती

हरिभूमि न्यूज: रायपुर
आने वाले दिनों में राज्य में ढाई सौ सीटें बढ़ने से एमबीबीएस की शासकीय सीटों की संख्या बढ़कर 1680 हो जाएगी। खुलने वाले पांच नए मेडिकल कालेजों में पढ़ाने के लिए कम से कम 100 चिकित्सा शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जिनकी व्यवस्था बड़ा चैलेंज है। राज्य में अभी संचालित दस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 1123 शिक्षकों की कमी है। इन्हें दूर करने संविदा भर्ती का ट्रिंक काम नहीं कर रहा है और सीधी भर्ती की प्रक्रिया अधूरी है। स्वास्थ्य सुविधा को आसान बनाने के लिए हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। अभी राज्य के दस जिलों में शासकीय मेडिकल कालेज संचालित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कबीरधाम, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा, गौदम और जशपुर जिले में नया कालेज खोलने की योजना पर काम पूरा किया जा रहा है। पचास-पचास सीटों के साथ शुरू

होने वाले इन चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1430 से बढ़कर 1680 हो जाएगी। सीट बढ़ने से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलेगा मगर इन्हें पढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षकों की व्यवस्था करना विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य में अभी संचालित होने वाले मेडिकल कालेजों में वैसे तो 10 शासकीय कालेजों में वैसे तो 2058 चिकित्सा शिक्षकों का संतअप है मगर उस पर काम करने वालों की संख्या 935 है और 1123 पद खाली पड़े हैं। चिकित्सा शिक्षकों की कमी को लेकर अक्सर एनएम्सी द्वारा आपत्ति की जाती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग शिक्षकों की इन कमियों को दूर करने के लिए लगातार संविदा पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन तो करता है, मगर भविष्य के लिए चिंतित डाक्टर इसके लिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। विभागीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग 125 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती सीजीपीएससी के माध्यम से कर रहा है इसके लिए आवेदन तो बुलाए गए हैं।

ये है दुनिया की सबसे छोटी हवाई यात्रा टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड बाद लैंडिंग

गिनीज बुक में दर्ज है रूट का नाम
अक्सर आपने सुना होगा कि फ्लाइट्स की यात्रा का समय घंटों का होता है लेकिन वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच की यह उड़ान सिर्फ 80 सेकेंड में ही पूरी हो जाती है और कई बार तो यह यात्रा सिर्फ 53 सेकेंड में भी पूरी हो जाती है। जिसके कारण ही इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है।
मात्र 2.7 किलोमीटर की फ्लाइट
दूरअसल, आज हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड के ऑकिनी द्वीप समूह में स्थित वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे द्वीपों के बीच की उड़ान की। यह उड़ान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे छोटी कॉमर्शियल फ्लाइट में रूप में दर्ज है। आपको बता दें कि इस यात्रा की दूरी सिर्फ 2.7 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में विमान को मात्र 80 सेकेंड लगते हैं। वहीं, अगर कभी हवा की दिशा अनुकूल हो तो इस फ्लाइट को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में सिर्फ 53 सेकेंड ही लगते हैं।

80 सेकेंड में आ जाती है गिनीज
अक्सर आपने सुना होगा कि फ्लाइट्स की यात्रा का समय घंटों का होता है लेकिन वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच की यह उड़ान सिर्फ 80 सेकेंड में ही पूरी हो जाती है और कई बार तो यह यात्रा सिर्फ 53 सेकेंड में भी पूरी हो जाती है। जिसके कारण ही इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है।
मात्र 2.7 किलोमीटर की फ्लाइट
दूरअसल, आज हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड के ऑकिनी द्वीप समूह में स्थित वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे द्वीपों के बीच की उड़ान की। यह उड़ान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे छोटी कॉमर्शियल फ्लाइट में रूप में दर्ज है। आपको बता दें कि इस यात्रा की दूरी सिर्फ 2.7 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में विमान को मात्र 80 सेकेंड लगते हैं। वहीं, अगर कभी हवा की दिशा अनुकूल हो तो इस फ्लाइट को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में सिर्फ 53 सेकेंड ही लगते हैं।

सुयश हॉस्पिटल
1 दिसंबर से 28 फरवरी तक
निसंतान दंपतियों के लिए निःशुल्क परामर्श
प्रथम 15 मंजिलीन में IVF/ICSI फंड में 20% की छूट
93000 30000 97551 62611
FOLLOW US ON
Dr. Nasser A. Nasser
MRCS, FRCS, Consultant Facial Plastic Surgeon
रिवाजती ढंग में सर्जरी, अग्रिम पंजीवन करवाये कलर्स माल के पास, पचपेदी नाका, रायपुर 98271 43060/8871003060
Ajay Pub.

पुलिस कमिश्नरेट का रिपोर्ट कार्ड, अपडेटेड पुलिस सिस्टम में भी चोरी के रिकवरी रेट में कोई सुधार नहीं

हरिभूमि न्यूज: रायपुर
राजधानी में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के साथ आसामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई पहले की तुलना में सौ से डेढ़ सौ प्रतिशत ज्यादा हुई है, लेकिन प्रायर्टी आफेंस चोरी, नकबजनी में अब तक अंकुश नहीं लग पाया है। नियमित पांच चोरी, उठाईगिरी की घटनाएं हो रही हैं। चोरी, उठाईगिरी में रिकवरी रेट वाहन चोरी को मिलाकर 24 प्रतिशत के करीब है। पिछले वर्ष की तुलना की जाए, तब भी राजधानी के साथ ग्रामीण थाना क्षेत्र में प्रतिदिन पांच से ज्यादा चोरी की घटनाएं होती थीं। राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुए एक माह हो गया। इस एक माह में पुलिस ने गुंडे-बदमाशों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए एक

अफसरों की फौज होने के बावजूद रिकवरी रेट 25 प्रतिशत से कम
महीने के अंदर एक हजार से ज्यादा गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। एक ओर पुलिस जहां गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं निगरानी बदमाशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से चोरी, उठाईगिरी का अपराध यथावत है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला का कहना है कि जितने निगरानी बदमाश हैं, उनकी नए सिरे से लिस्टिंग की जा रही है। निगरानी बदमाशों की लिस्टिंग होने के बाद निगरानी बदमाशों की निगरानी बहाई जाएगी। इससे चोरी की घटना पर आने वाले दिनों में अंकुश लगेगा। मारपीट, हत्या, लूट, डकैती से ज्यादा चोरी की

घटना सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती रहती है। हत्या, लूट, डकैती जैसे मामलों को सुलझाने का औसत सौ प्रतिशत तक पहुंच जाता है। चोरी, उठाईगिरी की घटना को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद 23 जनवरी से 22 फरवरी के बीच चोरी, उठाईगिरी के 146 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दर्ज किए गए प्रकरण में से 35 प्रकरण को पुलिस सुलझा पाई है। इस लिहाज से पुलिस ने दर्ज प्रकरण में से महज 24 प्रतिशत प्रकरण को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। लूट की घटना का औसत भी पूर्व की तरह है। पिछले वर्ष औसतन हर महीने छह लूट की घटनाएं दर्ज की गई थीं। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद एक महीने में छह लूट की घटनाएं हुई हैं। राहत की बात यह रही है कि लूट की घटना में से पुलिस ने पांच घटना को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।

संजीवनी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल
मूत्र रोग एवं पुरुष रोग विशेषज्ञ
डॉ. घनश्याम हटवार MS, MCh
की पूर्णकालिक सेवाएं अब उपलब्ध
विशेषज्ञता के क्षेत्र (Area of Expertise)
• पेशाब से जुड़ी समस्याएं
• किडनी की पथरी (किडनी स्टोन)
• प्रोस्टेट ग्रंथि संबंधी समस्याएं
• पेशाब नली में सिकुड़न (स्ट्रिक्चर)
• मूत्र रोग संबंधी कैंसर - किडनी, प्रोस्टेट
• अंडकोष व किंग की समस्याएं
• बिना चीरे के (Endoscopy) से इलाज
• पुरुष यौन समस्याएं
• हायपोस्पेडियास (वच्चों में नृत्रमार्ग विकृति)
9404310600
संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल कैम्पस UNIT 2, दावड़ा कॉलोनी, पचपेदी नाका, 7389955010, 04010

BALCO Medical Centre
बालको मेडिकल सेंटर
मध्यभारत का अत्याधुनिक व विश्वसनीय कैंसर हॉस्पिटल
NABH व NABL से मान्यता प्राप्त
• सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी
• डेट, स्केट स्कैन, HDT, LDT थेरेपी
• अत्याधुनिक ट्यू-बीम लिनक एवं हेल्थीऑन मरीन द्वारा रेडिएशन थेरेपी व ब्रैकिथेरेपी की सुविधा
• कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी
• रक्त-सम्बंधी सभी बीमारियां एवं वन मेरो ट्रांसफ्लांट
• आधुनिक रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी एवं ब्लड सेंटर
आपुष्मान भारत योजना से निःशुल्क ईलाज एवं सभी PSUs व बीमा कम्पनियों से अनुबंधित
सिटी सेंटर - बीएमसी कैंसर डेकेटर - कलर्स मॉल के बाजू, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.) 9201966330
मेन हॉस्पिटल - सेक्टर 36, नया रायपुर, छ.ग. 8282823333/4444